स्वदेशी पत्रिका

अ नु क्र म

वर्ष–26, अंक–5
वैशाख–ज्येष्ठ 2075, मई 2018

संपादक
अजेय भारती

सह–संपादक
अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा/उन्होंने कहा 4
समाचार परिक्रमा 34-38

तृतीय मुख्य पृष्ठ 39
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ 40

आवरण कथा – पृष्ठ–6

एयर इंडिया को बेचने पर हो पुनर्विचार

डॉ. अश्वनी महाजन

1 मुख्य पृष्ठ
2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 **पड़ताल**
मई दिवस: भारत में श्रम परिदृश्य
.... अनिल तिवारी

11 **विश्लेषण**
जलवायु संकट के बीच आंध्र से आशा की किरण
.... देविन्दर शर्मा

13 **बहस**
बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की चुनौतियां
.... दुलीचन्द रमन

15 **विमर्श**
अर्थव्यवस्था की विरोधाभासी चाल
.... भरत झुनझुनवाला

17 **समीक्षा**
देश को नशे में डूबने से बचाइए
.... भारत डोगरा

20 **पर्यावरण**
इन्द्रदेव की अगवानी की तैयारी ज़रूरी
.... अरूण तिवारी

23 **विचार**
लोकमत परिष्कार–एक जन आंदोलन
.... डॉ. विजय कुमार वशिष्ठ

25 **शिक्षा**
समग्र शिक्षा नीति की ओर–निर्णायक कदम (1)
.... डॉ. रेखा भट्ट

28 **स्वदेशी गतिविधियां**
राष्ट्रीय परिषद बैठक (अहमदाबाद, गुजरात)

38 **स्वदेशी गतिविधियां**
फ्लिपकार्ट–वालमार्ट सौदे के विरोध में स्वदेशी जागरण मंच

पाठकनामा

एससी/एसटी कानून पर झूठा बवाल

हिन्दी मासिक स्वदेशी पत्रिका का अप्रैल अंक मिला। एक तरफा नहीं चल सकता मुक्त व्यापार का कारोबार शीर्षक का आलेख बहुत की वाजिव और समसामयिक लगा। डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा दो टूक शब्दों में किया गया विश्लेषण कि अमरीका सरकार द्वारा संरक्षणवादी नीति अपनाने के बाद भारत सहित अन्य देशों को भी अपनी मुक्त व्यापार नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए, बहुत की सही और समय के मुताबिक की राय है। वास्तव में मुक्त व्यापार एकतरफा नहीं हो सकता। हमें अपनी व्यापार नीति अन्य देशों के रूख को देखते हुए बनानी पड़ेगी।

यह सही है कि मुक्त व्यापार सही और ईमानदार तरीके से लागू हो तो इसके फायदे सभी को मिलेगें। पर एंटी डंपिंग डयूटी व चीन जैसे देशों द्वारा की जा रही कारोगारी चालाकियों पर कानूनी नजर कड़ी करनी पड़ेगी। आज हालात यह है कि मात्र 20 वर्ष से कम की अवधि में ही दुनिया के अधिकांश हिस्सों में चीनी सामान भर गये हैं। रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं चीन निर्मित कर रहा है। चीन दुनिया का मैन्यूफेक्चरिंग हब बन गया है। हालांकि ट्रंप के आने के बाद से यह मुद्दा गंभीरता से ऊपर आया है, परंतु इसमें ईमानदार पहल की जरूरत है।

शिवाजी सरकार ने बैंकों के निजीकरण को देशहित के खिलाफ बताया है। उनका मानना है कि एक लावी जानबुझकर बैंकों के निजीकरण को हवा दे रही है। ऐसे लोगों का तर्क है कि निजीकरण से बढ़ते बैंक एनपीए और घोटालों से निजात पायी जा सकती है। उनका स्पष्ट मानना है कि बैंकों का निजीकरण एक बड़ी भूल होगी। पिछले 20 सालों में चिटफंड आपरेटरों ने अर्थव्यवस्था को कड़ा झटका दिया। अब ऐसे ही लोगों के हवाले बैंकों को कर देना न सिर्फ मूर्ख कदम होगा, बल्कि इसके परिणाम भी खासे खतरनाक होंगे।

देवेन्द्र शर्मा ने परंपरागत खाद्य फसलों की तरफ लौटने की वकालत करते हुए कहा है कि अगर समय रहते हम अपनी खेती में सुधार नहीं करते हैं तो हमारा भोजन दिन प्रतिदिन बेस्वाद और बेदम होता जायेगा। वहीं अरूण तिवारी द्वारा प्रमाण आधारित नीति नियोजन में मीडिया की भूमिका पर बेवाक टिप्पणी दमदार व अर्थपूर्ण है। उनका यह मानना है कि आंचलिक मीडिया जहां स्थानीय हकीकत से रूपक कराकर नीति निर्माताओं की दृष्टि विस्तृत कर सकता है, वहीं जनसंवाद का जनतांत्रिक मंच बनकर जनाकांक्षा से अवगत करान में अहम सहयोगी भूमिका अदा कर सकता है।

जयेंद्र नाथ मिश्र, *लक्ष्मीपुर, बलिया, उत्तर प्रदेश*

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्क: 15,00 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

हमें निर्यात बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। हमें दूसरे देशों में अपना माल डंप नहीं करना, गुणवत्ता के आधार पर उसे बेचना है। हमें कृषि, उद्योग और व्यापार में संतुलन बनाना होगा। भारत को अपने विकास मॉडल के आधार पर विश्व का नेतृत्व करना होगा।

परम पूजनीय मोहनराव भागवत
सरसंघचालक, आरएसएस

कृषि हमारे ग्रामीण विकास की कुंजी है। केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादकता और आत्म निर्भरता को विशेष महत्व देती है। नीम लेपित यूरिया ने किसानों को खासा लाभ पहुंचाया है।

नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री, भारत

दो मुख्य उभरते बाजारों, चीन और भारत, के बीच सहकार दुनिया को प्रभावित कर सकता है।

शी जिंनपिंग
राष्ट्रपति, चीन

गांवों के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं।

रवि शंकर प्रसाद
न्याय एवं कानून, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, भारत

सं
पा
द
की
य

बैंकिंग संकट पर न हो राजनीति!

लगभग 4 साल पहले जब रिजर्व बैंक के तत्कालीन गर्वनर रघुराम राजन ने यह कहा कि भारतीय बैंकिंग संकट में है, क्योंकि कुछ बड़ी कंपनियां अपने ऋणों का भुगतान नहीं कर पा रही हैं तो पूरा देश भौंचक्का रह गया था। जब अमरीका में सब–प्राइम संकट के चलते अमरीका ही नहीं पूरी दुनिया की बैंकिंग व्यवस्था चरमरा गई थी, उस समय भी भारत के बैंक न केवल मजबूती से खड़े थे बल्कि उनके लाभ भी बढ़ रहे थे। कुछ सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों के अपवाद को छोड़ दिया जाए तो भी भारत की बैंकिंग व्यवस्था दुनिया में एक मिसाल बन चुकी थी। भारत के नीति–निर्माता इस बात को लेकर गौरवांवित थे कि भारत का बैंकिंग सिस्टम दुनिया से अलग है, इसलिए शेष दुनिया की उठा–पटक इसे प्रभावित नहीं कर सकती। यह सही भी है कि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था अमरीकी और यूरोपीय व्यवस्था से काफी सुदृढ़ है। फिर भी पिछले लगभग चार सालों से भारतीय बैंकिंग एक बड़े संकट से गुजर रही है। भारत के निजी और सार्वजनिक दोनों तरह के बैंकों के एनपीए (नॉन परफारमिंग ऐसेट्स) 9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं। लेकिन सभी बैंकों में एक जैसी स्थिति नहीं है। कई बैंक भारी मात्रा में एनपीए से ग्रस्त हैं, जबकि कुछ अन्य बैंकों में समस्या इतनी गंभीर नहीं है। किसी भी ऋण के एनपीए होने के दो कारण हो सकते हैं। पहला, बैंकों में कुप्रबंधन के चलते बिना देखे अथवा जानबूझ कर जोखिम वाले कर्ज देना। दूसरा, अर्थव्यवस्था के धीमेपन के चलते कारपोरेट क्षेत्र द्वारा लिए गए ऋणों की अदायगी में कठिनाई।

पिछली सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन, घोटालों और कारपोरेट के साथ मिलीभगत के चलते कारपोरेट ऋणों के एनपीए होने के कई मामले सामने आए हैं। संभव है कि मंदी के चलते सही तौर पर दिए गए ऋणों की अदायगी में भी समस्या रही है, लेकिन बड़ी मात्रा में ऋणों के एनपीए होने का मुख्य कारण राजनीतिक नेतृत्व की मिलीभगत से उधार बांटना माना जा रहा है। विजय माल्या, नीरव मोदी समेत ऐसे कई उदाहरण देखने में आ रहे हैं जहां या तो उधार लेने वाले कारपोरेट की वित्तीय स्थिति को अनदेखा किया गया अथवा बैंकिंग प्रबंधन की लापरवाही अथवा मिलीभगत से घोटालों को रोका नहीं गया। बैंकों में तकनीकी क्षमता का अभाव भी घोटालों को समय पर न पकड़ पाने का एक बड़ा कारण रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली यूपीए सरकार का कार्यकाल घोटालों का कार्यकाल ही माना जाता रहा है। भारत के महालेखाकार और अंकेक्षक द्वारा कई घोटालों को उजागर किया गया जिनमें खास तौर पर कोयला घोटाला, 2–जी घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला शामिल हैं। ऐसे ही दूसरे घोटाले भी सामने आए। बैंकों में गलत प्रकार से ऋण देना भी उन्हीं घोटालों का एक विस्तार माना जा सकता है। जितने भी बैंकिंग घोटाले अथवा एनपीए उजागर हो रहे हैं, उनमें से लगभग सभी पूर्व सरकार के कार्यकाल में ही दिए गए थे। बैंकों में अधिकांश निदेशक सरकार अथवा रिजर्व बैंक द्वारा चयनित होते हैं, लेकिन घोटाले होने के बाद वे सभी लोग इससे पल्ला झाड़ लेते हैं। रोचक बात तो यह है कि इस प्रकार के लोगों के देश छोड़ के भाग जाने के बाद उसी दल के लोग जिनकी सरकार ने वे ऋण बांटे थे, वर्तमान सरकार पर मिलीभगत कर उन्हें भगाने का दोष मढ़ते रहे हैं। विपक्षी नेता ये कहते भी सुने जा रहे हैं कि सरकार डूब गये ऋणों को 'राइट आफ' यानी अपने खातों से हटाती जा रही है।

असलियत यह है कि 2017 में मात्र 13 प्रतिशत एनपीए ही राइट ऑफ किए गए, जबकि 2011 (यूपीए की सरकार के समय) में 25 प्रतिशत एनपीए राइट ऑफ किये गये थे। वर्ष 2016 में वर्तमान सरकार द्वारा नया दिवालिया कानून बनाया गया, जिसकी खासियत यह है कि कोई कंपनी या व्यक्ति यदि अपनी देनदारियों को तय समय में चुका पाने में असमर्थ रहता है तो एक निश्चित प्रक्रिया के अनुरूप एक कालखंड में उसकी परिसंपत्तियों को बेचकर ऋणदाताओं की भरपाई की जाएगी। इससे पहले किसी कंपनी या व्यक्ति को दिवालिया घोषित करने में एक लंबी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता था और उस कंपनी या व्यक्ति पर उधार और बोझ बढ़ता जाता था। भारत के कंपनी मामलों के विभाग के अनुसार दिवालिया कानून की बदौलत वर्ष 2017 में कुल 4 लाख करोड़ रुपए के एनपीए ऋणों की वापसी संभव हुई है। जानबूझ कर उधार न लौटाने वालों पर सख्ती से कार्यवाही हो रही है। पिछले वर्ष जून में 12 मामलों को रिजर्व बैंक ने कंपनी विभाग को सौंपा था, जिसमें से आधे मामलों में अच्छे परिणाम आए हैं। कहा जा सकता है कि एनपीए वसूली की प्रक्रिया जोर पकड़ रही है। यह जरूरी है कि बैंकों के निजीकरण की फिजूल की बहस में न पड़ते हुए लोगों का बैंकिंग सिस्टम में विश्वास पुनरू बहाल किया जाए। विपक्षी पार्टियों को भी चाहिए कि वे अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने की बजाय, बैंकिंग सिस्टम में लोगों का विश्वास बढ़ाने का प्रयास करें। यही समय की मांग है।

एयर इंडिया को बेचने पर हो पुनर्विचार

आज जब निजी क्षेत्र की बड़ी–बड़ी कंपनियों द्वारा लिए गए ऋणों की अदायगी में बैंकों द्वारा भारी छूटें दी जा रही हैं, एक सरकारी उपक्रम होने के कारण एयर इंडिया पर दोहरे मापदंड क्यों? क्यों उसे ये सुविधाएं नहीं दी सकती? सरकार को विचार करना चाहिए।

– **डॉ. अश्वनी महाजन**

पिछले कुछ समय से भारत के 'नैशनल कैरियर' एयर इंडिया के विनिवेश की कवायद चल रही है। बताया जा रहा है कि पिछले कई वर्षों से भारी घाटे में चलने के कारण यह सरकारी खजाने पर बोझ बनी हुई है। 1932 में जेआरडी टाटा ने टाटा एयरलाईंस के रूप में इसकी नींव रखी थी। तब से अब तक एयर इंडिया ने लाभ कमाते हुए भारी मात्रा में परिसंपत्तियां अर्जित भी की। वर्तमान में एयर इंडिया के पास 132 विमान हैं, और यह 94 भारत और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर उड़ान भरती है। अपनी प्रतिष्ठा के चलते दुनिया की जानी मानी एयर लाईंस के गठबंधन (स्टार एलाईंस) के सदस्य के रूप में एयर इंडिया शामिल है। अपनी शक्ति, सामर्थ्य, कुशलता और विशालता के कारण एयर इंडिया को महाराजा एयर लाईंस का भी खिताब स्वाभाविक रूप से मिल गया। दुनिया भर में 30 स्थानों पर लैंडिंग अधिकारों से लैस, एयर इंडिया के पास मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की बेहिसाब परिसंपत्तियां हैं। इसके साथ ही विमानों की पार्किंग के हजारों स्थान के रूप में कई ऐसे अधिकार हैं जिनकी गिनती संभव नहीं।

क्यों और कब घाटे में चली गई एयर इंडिया?

वर्ष 2007 में इन दोनों को मिलाकर एक इकाई एयर इंडिया लिमिटेड बना दी गई। विलय के समय एयर इंडिया और इंडियन एयर लाईंस की कुल हानि 770 करोड़ रूपए थी, जो 2009 तक आते–आते 7200 करोड़ रूपए (लगभग 9 गुणा) हो गई। एयर इंडिया में व्याप्त अकुशलता और ईंधन की बढ़ती कीमत ने एयर इंडिया की मुश्किलें कई गुणा बढ़ा दी। इन नुकसानों के चलते 2011 तक एयर इंडिया पर कुल कर्ज 42,900 करोड़ रूपए तक पहुंच गया। यह बावजूद इसके कि 2009 में कर्ज घटाने के लिए एयर इंडिया ने अपने कुछ विमान भी बेच दिए थे। दुनिया में कम एयर लाईंस ही ऐसी हैं जिनके पास विमानों के रख–रखाव और मरम्मत की सुविधा है। एयर इंडिया उस मामले में दुनिया की एक सुप्रसिद्ध कंपनी रही है। न केवल अपने विमानों का सही रख–रखाव कर लेती है, बल्कि निजी, घरेलू

एवं विदेशी विमानों का भी रख–रखाव और मरम्मत कर लेती है। इससे एयर इंडिया को केवल आमदनी ही नहीं होती, बल्कि अपने विमानों के रख–रखाव और मरम्मत के पैसे भी बचते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही कि पिछले लगभग 5–7 साल में एयर इंडिया की इस विशेषज्ञता पर ग्रहण लग गया। 2016 में एयर इंडिया ने अपना ईएएसए पंजीकरण भी खो दिया।

भ्रष्टाचार भी है कारण

एयर इंडिया में भ्रष्टाचार इस कदर व्याप्त रहा कि माना जाता है कि यह एयर इंडिया की बदहाली का मुख्य कारण है। पिछली यूपीए सरकार के समय जब एयर इंडिया को घाटे से उबारने के लिए एक बड़ी आर्थिक सहायता दी गई तो सरकार ने यह फैसला किया कि नए ड्रीम लाईनर हवाई जहाज एयर इंडिया के लिए खरीदे जाएं। लेकिन उस खरीद में भारी भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे। विमान बनाने वाली कंपनी ने जितने पैसे मांगे बिना मोलभाव किए विमान खरीद लिए गए, जबकि इस उद्योग में यह स्थापित है कि मोलभाव कर 35 से 40 प्रतिशत कम कीमत पर हवाई जहाज खरीदे जाते हैं। यही नहीं पहले से ही घाटे में चल रही कंपनी एयर इंडिया के लाभों वाले रूटों को बिना वजह दूसरी एयर लाईंस को दे दिया गया। इसमें भी भारी भ्रष्टाचार का अंदेशा है।

महाराजा के रहे शाही अंदाज

भारत और शेष दुनिया में जहां विमानन उद्योग बड़ी प्रतिस्पर्धा से गुजर रहा था, कई निजी और दूसरी देशों की सरकारों द्वारा चलाई जा रही विमानन कंपनियां घाटा भी सह रही थी, एयर इंडिया के शाही अंदाज देखने वाले रहे। इसके कुछ नमूने इस प्रकार से हैंः एयर इंडिया के हर सेवानिवृत अफसर को हर साल 18 हवाई यात्रा के टिकट मुफ्त, में दिए जाते हैं, जिसमें से 9 विदेशी यात्रा के हो सकते हैं। कार्यरत कर्मचारियों और अफसरों को तो एयर इंडिया से मुफ्त यात्रा की भारी सुविधा है ही। जब किसी भी वर्ष में एयर इंडिया में परिचालन लाभ बढ़ता है, तो एयर इंडिया के सभी कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी (इंक्रीमेंट) मिल जाती है। इसके अलावा भी कई और उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन खासियत यह है कि पिछले कई सालों से घाटा सह रही एयर इंडिया के यह शाही अंदाज बदस्तूर जारी रहे।

गत सालों में हुआ है सुधार

पिछले कई साल से एयर इंडिया में दूसरे कारणों से नुकसान तो रहा, लेकिन कुशलता के मापदंडों में खासी बेहतरी हुई है। यही नहीं, अब तो एयर इंडिया परिचालन लाभ की स्थिति में आ गया है, लेकिन फिर भी खातों में नुकसान इसलिए है क्योंकि उसे कर्ज और ब्याज की अदायगी में भारी रकम चुकानी पड़ती है। हालांकि एयर इंडिया में यात्री लोड, हवाई जहाज के प्रतिदिन घंटों की औसत संख्या विमान में भराव (आकुपेंसी) इत्यादि मापदंडों में भारी सुधार हुआ है। 2016–17 में नकदी घाटा 3991 करोड़ से घटता हुआ 2017–18 में मात्र 1674 करोड़ रह गया है। इस दौरान यात्रियों की संख्या में 15 लाख की वृद्धि और विमानन उपयोग के घंटों में भी खासी वृद्धि दिखाई देती है।

क्या विनिवेश है सही हल?

सरकार ने ऐसा मन बनाया है कि एयर इंडिया का 74 प्रतिशत हिस्सा किसी दूसरी कंपनी को देकर एयर इंडिया को आंशिक रूप से बेच दिया जाए। एयर इंडिया को बेचने के इस तरकीब में एयर इंडिया के परिसंपत्तियों को अलग रखा गया है। लेकिन जो कंपनी भी एयर इंडिया को खरीदेगी उसे इसका कर्जा भी लेना होगा। ऐसे में भारत की अधिकांश कंपनियों ने एयर इंडिया को खरीदने से अपने हाथ खींच लिए हैं। अभी केवल एक कंपनी, जिसने इसमें अपनी इच्छा जाहिर की है, वह है टाटा। लेकिन टाटा कंपनी भी सिंगापुर एयरलाईंस के साथ मिलकर ही इस काम को अंजाम दे सकती है। उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित कई संगठनों ने एयर इंडिया को विदेशी हाथों में सौंपने के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की है। एक ओर खरीदारों की अनइच्छा और दूसरी ओर नेशनल कैरियर को विदेशी हाथों में सौंपने के विचार के प्रति विरोध, सरकार को इस संबंध में अपनी रणनीति बदलने के लिए बाध्य कर सकते हैं।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि एयर इंडिया पर भारी कर्ज है, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि एयर इंडिया अपनी मूर्त एवं अमूर्त परिसंपत्तियों जैसे उसके कार्यालय, भूमि, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अधिकार आदि के कारण एक महाराजा एयर लाईंस है। वर्तमान के घाटे और कर्ज अकुशलता, भ्रष्टाचार और लापरवाहियों के कारण हैं। यदि अन्य एयर लाईंस की तर्ज पर एयर इंडिया में कुशलता के मापदंड बेहतर किए जाते हैं तो यह कंपनी जिसने 2016–17 में 298 करोड़ रूपए और 2017–18 में 140 करोड़ रूपए का परिचालन लाभ कमाया है, वह इससे कई गुणा ज्यादा लाभ कमा सकती है। यही नहीं हमे नहीं भूलना चाहिए कि एयर इंडिया पर कर्ज ब्याज के कारण भी ज्यादा बढ़ा है। भारत के मुख्य लेखाकार और अंकेक्षक (कैग) ने भी कुशलता के मापदंडों के अनुसार एयर इंडिया की बेहतर सेहत की तरफ इंगित किया है। ऐसे में एयर इंडिया को किन्हीं विदेशी हाथों में सौंपने की बजाय एक कुशल नेतृत्व की जरूरत है। नहीं भूलना चाहिए कि एक नेशनल कैरियर के नाते एयर इंडिया ने मुश्किलों के समय विदेशों

(शेष पेज 32 पर...)

मई दिवसः भारत में श्रम परिदृश्य

सन 1886 में मजदूरों ने पहली बार अमेरिका के शिकागो शहर में जब रैली निकाली थी, तो उनकी एक ही मांग थी कि काम के घंटे आठ होने चाहिए। पुलिस ने बर्बरता दिखाते हुए उन पर गोलियां चलाई, जिसमें कई मजदूर शहीद हुए। लड़ाई आगे भी चलती रही काफी उठापटक के बाद अंततः मजदूरों की बात मान ली गई। काम के घंटे आठ तय हो गए। मालिक बनाम मजदूर की तनातनी में बाजी मेहनतकश तबके के हाथ आई। इसी महान उपलब्धि को याद करते हुए दुनिया के अधिकांश देश 1 मई का दिन 'मई दिवस, श्रमिक दिवस, मजदूर दिवस' के रुप में मनाते आ रहे हैं। भारत में मई दिवस पहली बार वर्ष 1923 में मनाया गया। मजदूरों को जोड़े रखने तथा उनकी समस्याओं पर विचार करने के लिए मई दिवस का पहला आयोजन चेन्नई में हुआ था। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 132 वर्षों में दुनिया के साथ–साथ भारत में भी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सेवा शर्तों में काफी सुधार हुआ है। इन सुधारों से उनकी दशा और दिशा काफी हद तक बदली है, लेकिन देश में मजदूरों के बड़े क्षेत्र यानी असंगठित क्षेत्र के कामगारों की स्थिति निरंतर और अधिक बदतर तथा श्रमसाध्य होती गई है।

एक अनुमान के मुताबिक देश में कुल 45 से 46 करोड़ मजदूर है। जिनके जीवन में समस्याओं का अंबार है। इन मजदूरों में 95 प्रतिशत मजदूर असंगठित क्षेत्र के हैं। इन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के समक्ष जो समस्याएं पहले थी, कमोबेश वह अब भी मौजूद है। इन 132 वर्षों में गंगा यमुना में बहुत पानी बहा, परंतु मजदूरों की हालत आज भी जस की तस है। असंगठित क्षेत्र के मेहनतकश लोगों के लिए न तो कार्य के घंटे निर्धारित है और ना ही कोई वेतन आयोग है। उनके लिए रोज काम मिलने की निश्चितता भी नहीं है और ना ही भविष्य निधि अथवा पेंशन की कोई व्यवस्था है। उनके लिए न कोई नियम कानून है, ना ही कोई सामाजिक सुरक्षा। काम करने का सुरक्षित माहौल भी नहीं बन सका है।

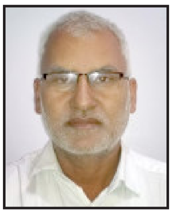

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के समक्ष जो समस्याएं पहले थी, कमोबेश वह अब भी मौजूद है। इन 132 वर्षों में गंगा यमुना में बहुत पानी बहा, परंतु मजदूरों की हालत आज भी जस की तस है।

– अनिल तिवारी

सन 1947 में जब देश आजाद हुआ तो यह माना गया कि आजाद भारत में मजदूरों के लिए दिन बहुरेंगे। शोषण खत्म होगा, उन्हें आवश्यक काम और काम के बदले उचित मजदूरी मिलेगी। पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए यह एक दिवास्वप्न की तरह ही रहा। उनके हिस्से कुछ नया नहीं आया। परिस्थितियां सुधरने की बजाय बद से बदतर होती गई। बोरिया, बिस्तर बांधकर परिवार समेत अपनी जड़ों से कटे प्रवासी श्रमिक अपने असली ठिकानों से बहुत दूर होते गए। महिला श्रमिकों के बड़े हिस्से को आज भी तवज्जो नहीं दी जाती।

केंद्र की मौजूदा एनडीए सरकार ने भारतीय श्रम परिदृश्य पर गंभीर मनन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 'मन की बात' कार्यक्रम के दौरान श्रमिक कल्याण और श्रम सुधार के मुद्दे को गंभीरता से उठाया। उन्होंने कहा कि चूंकि सरकार भारत को दुनिया में निवेश का सबसे बड़ा ठिकाना तथा सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए प्रतिबंद्ध है, इसलिए श्रम सुधारों को आर्थिक वृद्धि के अनुरूप बनाने एवं श्रमिकों का वास्तविक कल्याण सुनिश्चित करने की इच्छा के साथ श्रम सुधारों पर एतिहासिक दृष्टि डालने तथा आवश्यक परिवर्तन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सन 2025 तक भारत में दुनियाभर का सबसे बड़ा कार्यबल तैयार होने वाला है, इसलिए श्रमिकों की समस्याओं पर ध्यान देना और मान्य हल प्रस्तुत करना आवश्यक है। प्रधानमंत्री की पहल पर अमल करते हुए श्रमिक कल्याण के विभिन्न पहलुओं का ध्यान रखने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम, ठेका श्रमिक अधिनियम, जैसे कई कानून गत दिनों लागू किए गए हैं। इसके अलावा बोनस भुगतान विधेयक 2015, कर्मचारी वेतन संशोधन विधेयक 2016, बाल श्रम संशोधन विधेयक 2016 व 2017 पारित किए गए हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अब केंद्रीय श्रम कानूनों का सरलीकरण, एकीकरण करने व उन्हें तर्कसंगत बनाने के लिए नई श्रम संहिता तैयार की है। इसी तरह औद्योगिक संबंध विधेयक 2015 पर श्रम संहिता तथा सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य व महिला कामगारों के लिए कारगर कदम उठाया है। वर्तमान तथा भावी श्रमिक बल का सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें अपना ही कल्याण करने योग्य बनाने के लिए, मनरेगा, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन जैसी कई प्रकार की योजनाएं प्रारंभ की गई है।

भारत के श्रम मामले की एक और अहम बात श्रमिकों की खेती पर ज्यादा निर्भरता है। यहां 50 प्रतिशत से ज्यादा श्रमिक खेती पर निर्भर है। देश की जीडीपी में खेती का योगदान कम है, पर श्रमिकों की संख्या जरूरत से ज्यादा है।

आमतौर पर जगजाहिर है कि रोजगार के पर्याप्त अवसर और उसकी गुणवत्ता वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती रही है। भारत में भी ऐसा ही है और हाल के दिनों में यह चुनौती और बढ़ी है। आईएलओ की हालिया रिपोर्ट 'रोजगार और सामाजिक परिदृश्य 2017' में प्रमुखता से यह कहा गया है कि रोजगार की खराब गुणवत्ता दुनिया भर में ज्वलंत मसला है। दक्षिण एशिया और उप–सहारा अफ्रीका देशों में 80 प्रतिशत से ज्यादा कामगार असुरक्षित रोजगार के दायरे में है।

भारत की तकरीबन 1.3 अरब की आबादी, जो कि दुनिया की आबादी का छठवां हिस्सा है, में से 70 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं। इसमें से 40 से 45 प्रतिशत आबादी को कामकाजी आबादी की श्रेणी में रखा जा सकता है। यह अनुपात आजादी के बाद से कमोवेश एक जैसा ही रहा है। श्रमिकों की तादात में महिलाओं के अनुपात में पुरुषों के मुकाबले लगभग 20 प्रतिशत का अंतराल रहा है। हाल के अधिकारिक आंकड़ों में यह बढ़कर 25 से 30 प्रतिशत तक पहुंच गया है। आइएलओ में महिलाएं एवं काम 2016 नामक रिपोर्ट में पेश आंकड़ों के मुताबिक भारत में मजदूरी में लैंगिक अंतर अन्य देशों के मुकाबले 26 प्रतिशत अधिक है।

भारत के श्रम मामले की एक और अहम बात श्रमिकों की खेती पर ज्यादा निर्भरता है। यहां 50 प्रतिशत से ज्यादा श्रमिक खेती पर निर्भर है। देश की जीडीपी में खेती का योगदान कम है, पर श्रमिकों की संख्या जरूरत से ज्यादा है। खुद को किसान कहने वालों की तादात अब कम हो गई है। श्रमिकों की कुल संख्या में गैर कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी आधे के आसपास है लेकिन कुल जीडीपी में इसका योगदान 80 प्रतिशत है। इसमें संगठित क्षेत्र 10 प्रतिशत से भी कुछ कम ही है। संगठित क्षेत्र के कुल रोजगार में सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 65 से 70 प्रतिशत (प्रशासन और रक्षा सेवाएं) है। बाकी लगभग 3 करोड लोग निजी क्षेत्रों के लिए काम करते हैं, जिनमें मात्र 16 प्रतिशत संगठित क्षेत्र से है।

भारत दुनिया के समक्ष उभरती अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है, लेकिन कृषि क्षेत्र में रोजगार के घटने से निर्माण व कम कुशल सेवा क्षेत्र में असंगठित रोजगार बढ़ा है। विश्व व्यापार प्रतिस्पर्धा बढ़ने तथा संरक्षण पर सब्सिडी घटने से जोखिम बढ़ने लगा है। परिणामस्वरुप उद्यमियों ने अपने उद्यम

का आकार बढ़ने नहीं दिया। उन्हें नियम कानून का डर रहता है और श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा का सवाल भी। ऐसे में ठेका श्रमिकों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। हाल की आर्थिक जनगणना के अनुसार 6 से कम श्रमिकों वाली इकाइयों की संख्या 92 प्रतिशत से बढ़कर 96 प्रतिशत हो गई है, जबकि इस दौरान 10 से कम श्रमिकों वाली इकाइयों का प्रतिशत 3.5 से घटकर 3.1 प्रतिशत हो गया है।

रोजगार की बढ़ती हुई आकस्मिकता या संविदा से श्रमिकों की रोजगार सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। अब उन्हें न तो स्वयं और न ही परिवार के लिए चिकित्सा लाभ मिलता है। पेंशन मुआवजा, न्यूनतम वेतन, अतिरिक्त कार्य घंटों के लिए ओवर टाइम, सब कुछ समाप्त हो गया है। यहां तक कि व्यवसायिक जोखिमों की स्थिति में भी कोई लाभ नहीं मिलता।

बढ़ते असंगठित क्षेत्र की श्रमिक समस्याओं से निपटने के लिए हालांकि विभिन्न समितियों, आयोगों का गठन किया गया। समय–समय पर इनकी सिफारिशें भी आती रही, लेकिन नाकाफी रही है। कृषि क्षेत्र से निकले हुए श्रमिक नई अर्थव्यवस्था में अकुशल श्रमिक के तौर पर निर्माण कार्य में लग गए, गृह आधारित श्रमिक या सुरक्षा गार्ड बन गए, कुछ खुदरा व्यापारी बन गए। ऐसे में आयोगों की अधिकांश सिफारिशें श्रम कानून सुधार और कौशल प्रशिक्षण से संबंधित ही रही।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर कड़ा संज्ञान लिया तथा अपनी प्रतिबद्धता को आगे कर असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कवर देने के लिए अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कराया। इस योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को सदस्यता के आधार पर 1000 रूपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन प्रदान की जाती है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मात्र 12 रूपये सालाना प्रीमियम पर दो लाख रुपए का दुर्घटना एवं विकलांगत कवर प्रदान करती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना मात्र 330 रुपए के सालाना प्रीमियम पर दो लाख रूपये का जीवन बीमा कवर करती है। फसलों की क्षति से उबरने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सरकार भविष्य निधि में अपना अंश प्रदान करती है। वहीं कपड़ा क्षेत्र में वर्ष 2016 के बाद खोले गए खातों में सीधे 12 प्रतिशत का योगदान सरकार करेगी, कौशल भारत मिशन के तहत 20 से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया श्रम कानूनों का अनुपालन निरीक्षण को सरल बनाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक संख्या में उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहन मिले। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, जैसी प्रमुख योजनाओं से भी रोजगार सृजन की संभावना बनती है। इसके अतिरिक्त उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजनाओं जैसे स्टार्ट–अप इंडिया, स्टैंड–अप इंडिया, मुद्रा एस्पायर, अटल इनोवेशन मिशन, प्रधानमंत्री युवा योजना, आदि के माध्यम से भी अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न होने की उम्मीद है।

मजदूर दिवस के मौके पर 'मन की बात' में प्रधानमंत्री ने 'कर्म ही पूजा है' और 'जो बड़ी मेहनत करता है वह कभी भूखा नहीं रह सकता' का आदर्श वाक्य दोहराते हुए आश्वासन दिया कि असंगठित क्षेत्र श्रमिकों को अधिक से अधिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विधायी और योजनाबद्ध पहल की जाएगी।

मजदूर दिवस के मौके पर 'मन की बात' में प्रधानमंत्री ने 'कर्म ही पूजा है' और 'जो बड़ी मेहनत करता है वह कभी भूखा नहीं रह सकता' का आदर्श वाक्य दोहराते हुए आश्वासन दिया कि असंगठित क्षेत्र श्रमिकों को अधिक से अधिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विधायी और योजनाबद्ध पहल की जाएगी। नई नौकरियों की प्रकृति को और अधिक शिक्षा और सम्मानीय बनाने की जरूरत पर बल देते हुए उन्होंने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण के लिए संगठित क्षेत्र द्वारा उदारता दिखाने की अपील की। ❑❑

जलवायु संकट के बीच आंध्र से आशा की किरण

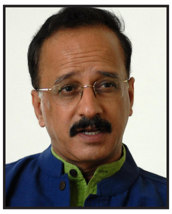

जर्मनी के एक संरक्षित वन में उड़ने वाले कीटों की तीन–चौथाई आबादी पिछले 25 वर्षों में गायब हो गई है। वहीं मधुमक्खियों की आबादी में खतरनाक गिरावट पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता व्यक्त हुई है। कीटों की 75 फीसदी आबादी लुप्त हो जाना और वह भी संरक्षित क्षेत्र में, वह 'पर्यावरण महाविनाश' की चेतावनी है।

– देविन्दर शर्मा

सारे सबूत सामने हैं। मिट्टी की उर्वरता घटने, भू–जल के जरूरत से ज्यादा दोहन से जलस्रोत सूख रहे हैं, कीटनाशकों सहित कई तरह के रसायन पर्यावरण में अत्यधिक फैल गए हैं और इनके कारण पूरी खाद्य श्रृंखला प्रदूषित हो गई है। मिट्टी रुग्ण होने और भूक्षरण के कारण मरुस्थल बढ़ रहा है। फसलों की उत्पादकता स्थिर हो गई है, जिससे उसी फसल को लेने के लिए अधिक रसायन डाले जा रहे हैं। भारतीय कृषि शोध परिषद के एक पूर्व महानिदेशक ने बताया, '1980 के दशक में किसान 1 किलो उर्वरक इस्तेमाल करके 50 किलो गेहूं पैदा करता था। अब किसान उतनी ही उर्वरक में मात्र 8 किलो गेहूं पैदा करता है।'

ऐसे में पर्यावरण संकट संबंधी एक चौंकाने वाला अध्ययन उपेक्षित ही रह गया। ससेक्स यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी के एक संरक्षित वन में उड़ने वाले कीटों की तीन–चौथाई आबादी पिछले 25 वर्षों में गायब हो गई है। वहीं मधुमक्खियों की आबादी में खतरनाक गिरावट पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता व्यक्त हुई है। कीटों की 75 फीसदी आबादी लुप्त हो जाना और वह भी संरक्षित क्षेत्र में, वह 'पर्यावरण महाविनाश' की चेतावनी है। यह एक ऐसे समय हो रहा है, जब न सिर्फ भारत के महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में बल्कि अमेरिका में भी जीएम कॉटन के प्रति खतरनाक बॉलवर्म कीट प्रतिरोधी हो गया है। कैलिफोर्निया से टैक्सस तक इन कीटों ने कॉटन पर ताजे हमले किए हैं।

हरित क्रांति की हवा पहले ही निकल गई है और विनाशक नतीजों का सिलसिला किसानों की आत्महत्या के रूप में सामने आ रहा है। जहां लागत बढ़ रही है, पर कीमतें

यदि कम नहीं भी हुई हैं तो स्थिर तो हैं ही और किसान की आय तेजी से घट रही है। अमेरिका में पिछले चार वर्षों में सैकड़ों डेयरी फार्म बंद हुए हैं। यूरोप में यदि सब्सिडी हटा दी जाए तो कई खेत मुनाफा देने लायक नहीं रहेंगे। फ्रांस में किसानों के 'म्युचुअल इंशोरेंस एसोसिएशन (एमएसए)' ने 2016 में कहा था, 'अधिसंख्य किसान प्रतिमाह 350 यूरो से कम कमाते हैं।' भारत में सरकार के ही आर्थिक सर्वेक्षण 2016 के मुताबिक 17 राज्यों में (यानी करीब आधा देश) किसान परिवारों की सालाना औसत आय मात्र 20 हजार रुपए रह गई है।

नीति आयोग का एक अन्य अध्ययन कहता है कि 2011 से 2016 के गत पांच वर्ष की अवधि में खेती की आय स्थिर रही है। सारे प्रशंसनीय लक्ष्यों के बावजूद दुनिया लगभग संकट के बिंदु पर पहुंच गई है जिसकी 'इंटरनेशल पेनल ऑन क्लाइमेंट चेंज' ने कुछ साल पहले चेतावनी दी थी। यहां तक कि इंटरनेशनल असेसमेंट फॉर एग्रीकल्चरल नॉलेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट (आईएएएसटीडी) ने तत्काल टिकाऊ खेती की ओर जाने की जरूरत बताई है, जो बहुत समय से अधर में है। हर विनाश एक अवसर होता है लेकिन, यह अपरिहार्य रूप से बिजनेस के अवसर के रूप में सामने आता है।

पर्यावरण पर आलाप के समान समाधान भी वही बने हुए हैं : औद्योगिक कृषि के लिए अधिक दबाव। दुनिया में 2008 जैसा खाद्य संकट फिर पैदा न हो –जब 37 देशों में खाद्यान्न को लेकर दंगे हुए थे– यह सुनिश्चित करने के लिए बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने एक रोडमैप प्रस्तुत किया। यह कोई एक रोडमैप नहीं बल्कि निजी क्षेत्र द्वारा संचालित कई रूपरेखाएं हैं। 2009 के विश्व आर्थिक मंच पर 17 निजी कंपनियों के बिजनेस लीडर्स ने एक नया मंच जारी करने घोषणा की थी। नाम था– 'न्यू विजन फॉर एग्रीकल्चर'।

पर्यावरण को जरा भी नुकसान पहुंचाए बगैर किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौटाने वाली टिकाऊ खेती की पटकथा लिखी जा रही है। आंध्र प्रदेश ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का विशाल कार्यक्रम शुरू किया है।

इसमें हर दशक में खाद्यान्न में 20 फीसदी उत्पादन बढ़ाने, प्रतिटन ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन 20 फीसदी गिराने और ग्रामीण गरीबी को 20 फीसदी घटाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य सामने रखा गया है। इन 17 कृषि–उद्योग की दिग्गज कंपनियों में आर्टर डेनियर्स मिडलैंड, बीएएसएफ, बंज लिमिटेड, कारगिल, कोका–कोला, ड्यू पॉइंट, यूनिलिवर, वाल–मार्ट आदि शामिल हैं। दूसरे शब्दों में दुनिया जितनी बदलने की कोशिश करती है, उतनी वह वहीं बनी रहती है।

इस कठिन समय में यह देखकर अच्छा लगा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दुनिया के सामने खड़े पर्यावरण संकट को पहचाना है। अक्टूबर में कम्युनिस्ट पार्टी की नेशनल कांग्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने माना था, 'प्रकृति को हम जो भी नुकसान पहुंचाएंगे, वह लौटकर हमें ही संकट में डालेगा... यह ऐसी वास्तविकता है, जिसका हमें सामना करना है।' उसके बाद उन्होंने हरित, कम कार्बन वाले और चक्राकार विकास की दिशा में कानूनी व नीतिगत ढांचा तय करने के प्रयास तेज करने के ब्योरे दिए। इसका उद्देश्य वेटलैंड का संरक्षण व बहाली और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली सारी गतिविधियों को रोकना और दंडित करना है। उन्होंने 21वीं सदी में 'इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन' की शुरुआत का आह्वान किया।

हमारे देश में पर्यावरण को जरा भी नुकसान पहुंचाए बगैर किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौटाने वाली टिकाऊ खेती की पटकथा लिखी जा रही है। आंध्र प्रदेश ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का विशाल कार्यक्रम शुरू किया है। 'रायथु साधिकारा सम्स्था' नामक इस कार्यक्रम में 2017–2022 की अवधि में सभी 13 जिलों के 5 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती पर लाने का उद्देश्य है। मैं हाल ही में कुरनूल जिले के कई गांवों में उन किसानों से मिला हूं, जो रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती पर आ गए हैं।

मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि सारी फसलों में उपज बढ़ी है। मुंगफली में उत्पादन 35 फीसदी, कॉटन में 11 फीसदी, मिर्च में 34 फीसदी, बैंगन में 69 फीसदी और धान में 10 से 12 फीसदी वृद्धि हुई है। अब तक 1.63 लाख किसान प्राकृतिक खेती की ओर मुड़े हैं। यदि रासायनिक खाद व कीटनाशकों का इस्तेमाल किए बिना उत्पादन बढ़ाया जा सकता हो, यदि किसानों की शुद्ध आय बढ़ती हो और यदि प्राकृतिक खेती से जलवायु परिवर्तन का सामना करने वाली खेती की शुरुआत होती हो तो कोई कारण नहीं कि अन्य राज्य आंध्र प्रदेश द्वारा किए गए नई जमीन तोड़ने वाले प्रयासों का अनुसरण न करें। ❑❑

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की चुनौतियां

कभी विश्व में थानेदार की भूमिका निभाने वाला अमेरिका आज कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है। ये अमेरिका की फितरत है कि वह कभी शांत नहीं बैठ सकता। चाहे वियतनाम, जापान, अफगानिस्तान, अरब देशों के साथ युद्व का इतिहास रहा हो, या सोवियत संघ से लंबा शीत युद्व। अमेरिका अमुमन हर वैश्विक संघर्ष में एकपक्ष रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अमेरिका ने कई नये मोर्चे भी खोल दिये है। इन मोर्चों पर लड़ाई के आयाम भी अलग–अलग है। चूंकि ट्रंप की पृष्ठभूमि एक उद्योगपति की रही है, इसलिए उसके सोचने का नजरिया भी अमेरिका के पूर्व के राष्ट्रपतियों से थोड़ा अलग है।

ट्रंप चीन के साथ 32.5 लाख करोड़ के व्यापार घाटे को लेकर चिंतित है। वह जानता है कि चीन ने ऐसी आर्थिक और व्यापारिक बढ़त बना ली है जिससे अमेरिका सकपकाया हुआ है। एक अनुमान के अनुसार चीनी अर्थव्यवस्था सन् 2030 तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पछाड़ देगी। अमेरिका को बढ़ते व्यापार घाटे की इतनी चिंता नहीं होती अगर चीन सिर्फ एक व्यापारी देश ही होता। अमेरिका चीन की सैन्य महत्वकांक्षाओं से बेखबर नहीं है। एक समय वो था जब अमेरिका आई.एम.एफ, विश्व बैंक तथा विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाओं के माध्यम से बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की धुरी था। आज अमेरिका जब घरेलू उद्योग व रोजगार बचाने के लिए चीनी सामान के आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगाता है तो चीन उसे उसी खुली प्रतिस्पर्धा की दुहाई देता है।

डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सरकार इस व्यापार युद्व में खुलकर आमने–सामने आ चुके है। अप्रैल 2018 के प्रथम सप्ताह में जब ट्रंप प्रशासन ने चीन से आयात पर 50 बिलियन डालर अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा तो सिर्फ ग्यारह घंटों में ही चीन ने बदले की कार्यवाही करते हुए अमेरिका से आयतित 106 वस्तुओं पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क

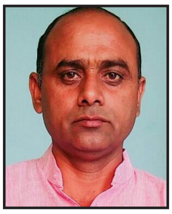

अमेरिका की फितरत है कि वह कभी शांत नहीं बैठ सकता। चाहे वियतनाम, जापान, अफगानिस्तान, अरब देशों के साथ युद्व का इतिहास रहा हो, या सोवियत संघ से लंबा शीत युद्व। अमेरिका अमुमन हर वैश्विक संघर्ष में एकपक्ष रहा है।

– **दुलीचन्द रमन**

लगाने की धमकी दे दी। चीन ने इस व्यापार युद्व में ट्रंप के खिलाफ राजनीतिक चाल भी चल दी है। शुल्क बढ़ोतरी में सोयाबीन को भी शमिल कर लिया जिसका निर्यात अमेरिका से चीन को 12 बिलियन डालर का होता है। अगर यह निर्यात प्रभावित हुआ तो यह अमेरिका के उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बैचेनी पैदा करेगा, जहां से ट्रंप को सबसे ज्यादा वोट मिले थे।

दूसरा मोर्चा उत्तर कोरिया का है, जो अमेरिका के साथ वैसे तो वार्ता के लिए तैयार हो गया है लेकिन उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग ने पहले तो शीतकालीन खेलों के माध्यम से कूटनीतिक पहल करके दक्षिण कोरिया से संबंधों को सामान्य करने का प्रयास किया तथा फिर गुप–चुप तरीके से ट्रेन के माध्यम से चीन की यात्रा करके वार्ता का परिदृश्य ही बदल दिया। चीन कभी भी नहीं चाहेगा कि अमेरिका की परेशानियां कम हो। उत्तर कोरियाई शासक को चीन का आशीर्वाद ट्रंप–किम जोंग वार्ता में उत्तर कोरिया को बल प्रदान करेगा। इस वार्ता में अप्रत्यक्ष रूप में चीन की भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि उत्तर कोरिया व्यापार और अर्थव्यवस्था के मामले में चीन पर आश्रित है।

अफगानिस्तान का मोर्चा भी जीत से कोसों दूर है। तालिबान अभी भी अफगानिस्तान में अपनी पैठ बनाये हुए है। अफगानिस्तान की सरकार की विश्वसमीयता पर उनके ही देश में प्रश्न चिन्ह लगे है। तालिबान को साधने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान पर शिंकजा कस दिया था। पाकिस्तान को दी जा रही आर्थिक व सैन्य सहायता पर अंकुश लगा दिया तो पाकिस्तान ने अपना पाला बदल लिया अैर चीन की शरण में चला गया।

एक अन्य मोर्चा रूस के साथ है। रूस द्वारा अपने एक पूर्व–जासूस को ब्रिटेन में जहर देने की घटना के बाद पश्चिमी देशों और रूस के बीच राजनायिकों के निष्कासन की होड़ ही लग गई। अमेरिका व कई अन्य पश्चिमी राष्ट्रों ने 150 रूसी राजनायिकों को निष्कासित कर दिया। अमेरिका और रूस के हित सीरिया में जारी संघर्ष में भी एक दूसरे से टकरा रहे है। राजधानी दमिश्क में राष्ट्रपति असद समर्थित सेना द्वारा रासायनिक हथियारों के प्रयोग के कारण अमेरिका, फ्रांस तथा बिट्रेन ने संयुक्त रूप से बदले की कार्यवाही करते हुए सीरिया पर मिसाईल हमले भी किये हैं। रूस अगर इन हमलों का जवाब देता है तो ये तीसरे विश्व युद्व की आहट होगी।

अमेरिका में साफ्टवेयर क्षेत्र में काम कर रही भारतीय कंपनियों पर अमेरिकी नागरिकों को रोजगार देने के लिए दबाव डालने जैसे कई फैसले द्विपक्षीय संबंधों पर काली छाया की तरह रहे है।

भारत को ट्रंप प्रशासन रणनीतिक सांझेदार के रूप में देखता है। इसके साथ–साथ व्यापारिक मोर्चे पर दो–दो हाथ करने के मूड़ में है। पिछले दिनों अमेरिका निर्मित हार्ले–डेविडसन मोटर साईकिल पर भारत द्वारा आयात शुल्क का मुद्दा बनाना, स्टील व एल्युमिनियम आयात पर अमेरिका द्वारा अतिरिक्त आयात शुल्क थोपने के कारण भारतीय इस्पात उद्योग के लिए समस्या खड़ी हो सकती है। अमेरिका में साफ्टवेयर क्षेत्र में काम कर रही भारतीय कंपनियों पर अमेरिकी नागरिकों को रोजगार देने के लिए दबाव डालने जैसे कई फैसले द्विपक्षीय संबंधों पर काली छाया की तरह रहे है। लेकिन भारत अब किसी एक देश का पिछलग्गू नहीं रह गया है। ये बात अमेरिका को भी समझ में आ चुकी है। भारत शीत युद्व के दौरान की केचुल भी उतार चुका है। हथियारों के मामले में सिर्फ रूस पर निर्भरता खत्म हो चुकी है। अब हम पश्चिम के देशों की यात्रा सिर्फ वित्तिय अनुदान के लिए ही नहीं करते।

भारत के पड़ोस में अमेरिका का सीधा टकराव केवल चीन से है। जिसके साथ दक्षिण चीन सागर में कई मुद्दों पर उसका विवाद चल रहा है। भारत हिन्द–प्रशांत क्षेत्र एक मजबूत नौ–सैनिक शक्ति है। इस क्षेत्र में चीन को रणनीतिक रूप से साधने में भारत की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो जाती है। जिसे अमेरिका नज़र अंदाज नहीं कर सकता।

उत्तर–कोरिया तथा सीरिया में अमेरिकी टकराव चीन और रूस को और पास लाने का कारण बनेगा। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में विश्वसनियता कम होती जा रही है जबकि पुतिन और शी जिनपिंग की सत्ता को उनके देशों में फिलहाल कोई चुनौती नहीं है। अगर दूसरा शीत युद्व शुरू हुआ तो इसमें वपार मुख्य मुद्दा रहेगा। जाहिर है नई व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नये नियम व संस्थायें वजूद में आयेगी। भारत के लिए वैश्विक तनातनी के इस माहौल में बहुत संभल कर चलने का समय है। रूस हमारा मित्र देश रहा है। जिससे हम अभी तक रक्षा सामग्री लेते रहे है। चीन जैसी अविश्वसनीय सैन्य व आर्थिक शक्ति हमारे पड़ोस में है जिसको नज़र अंदाज़ नहीं किया जा सकता।

विश्व स्तर पर वर्चस्व की लड़ाई में भारत के लिए कई चुनौतियां तो आयेगी ही, मगर कई अवसर भी पैदा होंगे। हमें टकराव में भी सहयोग के रास्ते ढूंढ़ने होगें। क्योंकि कभी–कभी तनाव भी विदेश नीति का एक हथियार होता है। ❑❑

अर्थव्यवस्था की विरोधाभासी चाल

इस समय अर्थव्यवस्था में शुभ और अशुभ दोनों तरह के विरोधाभसी संकेत मिल रहे हैं। तीन शुभ संकेत हैं। पहला शुभ संकेत है कि जीडीपी यानि सकल घरेलू उत्पाद यानि देश की आय की विकास दर पुनः पटरी पर आ रही है। बीते समय में यह 6 प्रतिशत से नीचे चली गई थी जो अब पुनः 6 से 7 प्रतिशत के बीच में पुरानी चाल पर आ गई है। दूसरा शुभ संकेत है कि वर्ष 2016–17 मे 60 अरब डालर सीधा विदेशी निवेश भारत में आया था जो ऐतिहासिक अधिकतम है, जिससे संकेत मिलता है कि विदेशी निवेशकों को भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा बन रहा है। तीसरा शुभ संकेत है कि डालर के सामने रुपया 65 रुपये प्रति डालर के इर्द गिर्द टिका हुआ है। इसके विपरीत तीन ऐसे संकेत भी मिलते हैं जो अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत का बयान करते हैं। पहला संकेत है कि बैंकों द्वारा दिये जाने वाले लोन में वर्ष 2016–17 में मात्र 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुयी थी जो पिछले 60 वर्षों की न्यूनतम वृद्धि है। यानि हर वर्ष बैंकों द्वारा दिये गये लोन में जो बढ़त होती है वह इस समय गिर रही है। खस्ता हालत का दूसरा संकेत है कि संगठित क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न होने में भारी गिरावट आयी है। वर्ष 2011 तक अर्थव्यवस्था में आठ लाख रोजगार प्रतिवर्ष बन रहे थे जो वर्तमान में दो लाख पर आ टिका है। खस्ता हालत का तीसरा संकेत है कि बैंकों द्वारा दिये गये ऋण में नान–परफार्मिंग एसेट यानि खटाई में पड़े ऋण की मात्रा लगातार बढ़ रही है। इन दोनों विरोधाभासी संकेतों को समझने के लिये हम प्रयास करेंगे।

मेरे आकलन में अर्थव्यवस्था में मूलतः मंदी छायी हुयी है। प्रमाण यह है कि बैंकों द्वारा दिये जा रहे लोन में गिरावट आयी है, रोजगार सृजन में गिरावट आयी है तथा बैंकों के नान पर्फामिंग ऐसेट बढ़ रहे हैं। मैंने देश के कुछ बड़े उद्यमियों से बात की तो उनमें मैंने निराशा की झलक पायी। जैसे एयरटेल कंपनी के मालिक सुनिल भारती मित्तल ने एक सार्वजनिक समारोह में कहा कि विदेशी निवेशक 60 अरब डालर सीधा विदेशी निवेश भारत में हर वर्ष

जीडीपी यानि सकल घरेलू उत्पाद यानि देश की आय की विकास दर पुनः पटरी पर आ रही है। बीते समय में यह 6 प्रतिशत से नीचे चली गई थी जो अब पुनः 6 से 7 प्रतिशत के बीच में पुरानी चाल पर आ गई है।

डॉ. भरत झुनझुनवाला

ला रहे हैं, यह दिखाता है कि वे भारत को निवेश का एक अच्छा स्थान मान रहे हैं। फिर उन्होंने कहाः तब भारतीय उद्यमियों में उत्साह क्यों नहीं है यह हमें पूछने की जरूरत है। इसका अर्थ यह हुआ कि कहीं न कहीं जो विदेशी निवेश आ रहा है उसमें कुछ समस्या है। गहराई से पड़ताल करने पर पता लगता है कि देश में आने वाला विदेशी निवेश संकटग्रस्त घरेलू कंपनियों को खरीदने के लिये अधिक और नये निवेश करने के लिये कम आ रहा है। जैसे यदि मान लीजिये भारत की कोई कंपनी संकट में है तो विदेशी निवेशक उसको कम दाम में खरीद लेते हैं और इसके लिये वे विदेशी निवेश ला रहे हैं। वे इसलिये विदेशी निवेश नहीं ला रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी है ओर यहां आने वाले समय में माल की बिक्री बढ़ेगी और कारोबार करने का अवसर बढ़ेगा। बल्कि जैसे अस्पताल में भर्ती परिजन को देखने के लिये लोग यात्रा करते हैं उस तरह विदेशी निवेश आ रहा हैं, इसलिये नहीं कि परिवार के लोग पर्यटन के लिये आये हैं और उनसे मिलने जायें। 'दी वायर' नामक न्यूज पोर्टल के अनुसार अमरीकी कंपनी अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट और दूसरी कनेडियन कंपनियों ने विशेष फंड बनाये हैं जो कि भारत की संकटग्रस्त कंपनियों को खरीदने में निवेश कर रही हैं। एक और संकेत इस बात से मिल रहा है कि वर्ष 2015 में देश में आने वाले विदेशी निवेश का केवल 25 प्रतिशत वर्तमान कंपनियों को खरीदने में लगा था। वर्ष 2016 में यह हिस्सा बढ़कर 45 प्रतिशत हो गया। यानि विदेशी निवेश नई कंपनियों को स्थापित करने में कम ओर पुरानी कंपनियों को खरीदने में जादा आ रहा है।

'दी वायर' नामक न्यूज पोर्टल के अनुसार अमरीकी कंपनी अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट और दूसरी कनेडियन कंपनियों ने विशेष फंड बनाये हैं जो कि भारत की संकटग्रस्त कंपनियों को खरीदने में निवेश कर रही हैं।

दूसरा कथित सकारात्मक संकेत सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का था। यह बात सही है कि जीडीपी की ग्रोथ रेट 6 प्रतिशत से बढ़कर वर्तमान में 7 प्रतिशत के करीब पुनः आ गई है। लेकिन यह प्रसन्न होने की बात नहीं है। वर्तमान सरकार ईमानदार है। बुनियादी संरचना में निवेश तेजी से हुआ है। अतः देश की ग्रोथ रेट को बीते समय के 7 प्रतिशत से बढ़कर वर्तमान में 9, 10 या 12 प्रतिशत होना चाहिये था। सरकार की कार्यकुशलता के कारण अर्थव्यवस्था में जो तेजी आनी थी वह तेजी नहीं आयी है। यही संकट है। सरकार की कार्यकुशलता के कारण जो सुधार होना था वह वह सरकार की ही दूसरी नकारात्मक पॉलिसियों के कारण कट गया है। अतः ग्रोथ रेट का पुनः 6 से 7 प्रतिशत पर आ जाना वास्तव में ढपली बजाने वाली बात नहीं है। इसको मंदी के बने रहने के रूप में देखा जाना चाहिये।

तीसरा कथित सकारात्मक बिन्दु रुपये के मूल्य का टिका रहना है। इसका कारण यह है कि हमारे निर्यात् दबाव में हैं और निर्यातों से डालर हम कम मात्रा में अर्जित कर रहे हैं। परंतु हमारी संकटग्रस्त कंपनियों को खरीदने के लिये विदेशी निवेश ज्यादा मात्रा में आ रहा है और डालरों की उस आवक के कारण हमारा बाहरी मुद्रा खाता बराबर हो गया है। ऐसा समझें कि परिवार संकट में है। परिवार के लोग बीमार हैं। उन्हें देखने के लिये कई डाक्टर टैक्सी से आ रहे हैं। तो दूर से ऐसा दिखेगा कि परिवार में बड़ी चहल पहल है और इसे कोई शुभ संकेत भी मान सकता है, इस प्रकार की परिस्थिति है।

सारांश यह है कि मूल रूप से देश की अर्थव्यवस्था संकट में है। ग्रोथ रेट न्यून है और सरकार की ईमानदारी का दोहरा प्रभाव पड़ रहा है। एक तरफ सड़क आदि बनाने में प्रगति हुयी है तो दूसरी तरफ आधार, जीएसटी और नोटबंदी ने उन शुभ प्रभावों को काट दिया है। लेकिन अर्थव्यवस्था का यह संकट पूरी तरह दिख नहीं रहा है क्योंकि संकटग्रस्त कंपनियों को खरीदने के लिये विदेशी निवेशक भारी मात्रा में आ रहे हैं जिससे कि हमारा रुपये का मूल्य टिका हुआ है। हमें गलत एहसास हो रहा है कि अर्थव्यवस्था में सबकुछ ठीक है जबकि अर्थव्यवस्था मूल रूप से गड़बड़ दिशा में चल रही है। ❑❑

देश को नशे में डूबने से बचाइए

1. विश्व स्तर की पृष्ठभूमिः दुनिया भर से प्राप्त हो रहे नए अनुसंधान से दो तथ्य स्पष्ट हो रहे हैं। शराब से होने वाले स्वास्थ्य व सामाजिक दुष्परिणाम अति गंभीर हैं। अनेक नए गंभीर दुष्परिणामों का भी पता चल रहा है–

- विश्व स्वास्थ्य संगठन की शराब व स्वास्थ्य स्टेटस रिपोर्ट (2014) के अनुसार विश्व में वर्ष 2012 में शराब से 33 लाख मौतें हुईं।
- इस रिपोर्ट ने यह भी बताया है कि 200 तरह की बीमारियों व चोटों में शराब का हानिकारक उपयोग एक कारण है।
- नशीली दवाओं, एल्कोहल व एडिक्टिव बिहेवियर के विश्व कोष के अनुसार मौत होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में से 44 प्रतिशत में एल्कोहल की भूमिका पाई गई है।
- विभिन्न देशों में होने वाले अध्ययनों में यह महत्त्वपूर्ण तथ्य सामने आया है कि 50 प्रतिशत से अधिक यौन हिंसा व हमलों में शराब व नशीली दवाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।
- यूरोपीयन यूनियन के लिए वर्ष 2003 में लगाए गए अनुमान में शराब के सामाजिक दुष्परिणामों की कीमत 125 अरब यूरो लगाई गई।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए वर्ष 2006 में शराब के सामाजिक दुष्परिणामों की कीमत 233 अरब डालर लगाई गई।

शराब के इन अति गंभीर दुष्परिणामों के नए तथ्य सामने आने के बावजूद शराब व्यवसाय से जुड़ी ताकतें व उनके पैरोकार तरह–तरह से शराब की खपत बढ़ाने के नए तौर–तरीके फैलाने में लग गए हैं। यदि गंभीर दुष्परिणामों के बारे में जानकारी मिलने से एक व्यक्ति शराब छोड़ता है, तो शराब उद्योग व उसके पैरोकारों का कुप्रयास यह होता है कि किसी तरह नए व्यक्तियों को शराब की लत लगा दें। इसके लिए वे इस तरह के नए तरीकों को उपयोग कर रहे हैं जिससे कि शराब के काल्पनिक स्वास्थ्य लाभ बताए जाएं व शराब की मान्यता किसी नए रूप में उन लोगों में बढ़ा दी जाए जो पहले शराब नहीं पीते थे।

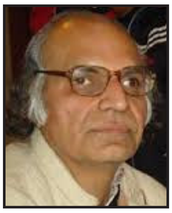

शराब के गंभीर दुष्परिणामों के बारे में जानकारी मिलने से एक व्यक्ति शराब छोड़ता है, तो शराब उद्योग व उसके पैरोकारों का कुप्रयास यह होता है कि किसी तरह नए व्यक्तियों को शराब की लत लगा दें।

– **भारत डोगरा**

इस तरह अनेक देशों में रेड वाईन के प्रसार को बताया गया। रेड वाईन गहरे रंग के अंगूरों को पीस कर व फिर उनका फरमंटेशन कर तैयार की जाती है। इसकी एल्कोहल मात्रा 14 प्रतिशत है जो बीयर की औसत एल्कोहल मात्रा से लगभग तीन गुणा अधिक है। फोर्टीफाइड वाइन में एल्कोहल की मात्र 22 प्रतिशत तक हो सकती है यानि बीयर से पांच–छः गुणा भी अधिक हो सकती है। बीयर के सेवन से अनेक दुष्परिणाम होते हैं, नशा होता है, लत की ओर बढ़ सकते हैं तो वाईन के बारे में यह सब और भी सच है। सामान्यतः शराब से जुड़े जो भी दुष्परिणाम होते हैं वे वाईन व रेड वाईन पर भी लागू होते हैं।

विश्व में स्वास्थ्य अभियानों व नशा–विरोधी अभियानों के कारण हार्ड लिक्वर यानि विहस्की, वोदका, रम आदि की बिक्री को बढ़ाने की कुछ सीमाएं हैं। इस स्थिति में कुछ शक्तिशाली व साधन संपन्न तत्त्वों ने यह निर्णय लिया कि वाईन विशेषकर रेड वाईन को एक ऐसी ड्रिंक के रूप में प्रचारित किया जाए जो सामान्य शराब से कुछ हट कर है, जिसके दुष्परिणाम बहुत कम है बल्कि स्वास्थ्य लाभ भी है। यह तथ्य पूरी तरह गलत थे पर निहित स्वार्थों के इन गलत तथ्यों को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके साथ वाईन को 'गुड लाईफ' व 'रोमांस' के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया गया।

ऐसे प्रचार–प्रसार का परिणाम यह हुआ कि लाखों व्यक्ति जो हार्ड लिक्वर का सेवन नहीं करते थे या नशा कम करते थे अब बहुत खुले मन से रेड वाईन का सेवन करने लगे। जो सावधानियां हार्ड लिक्वर के मामले में बहुत से व्यक्ति अपनाते थे, मिथ्या प्रचार के असर में उन सावधानियों को भी त्यागने लगे। बहुत से लोगों ने यह आदत बना ली कि दिन भर के काम से घर लौटने पर एक गिलास वाईन वे पीते थे और कई बार तो इससे अधिक भी पी लेते थे।

इस संदर्भ में वाईन के एल्कोहल मात्र की ओर ध्यान दिलाते हुए ब्रिटेन के प्रमुख स्वास्थ्य कार्यकर्ता पब्लिक हैल्थ के डंकन सैलबी ने ध्यान दिलाया कि एक गिलास रेड वाईन वोदका की तीन शॉट के बराबर है। उन्होंने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि वर्ष 1970 के बाद के दौर में लिवर के गंभीर मरीजों की संख्या में ब्रिटेन में 500 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है व इसमें शराब के बढ़ते चलन की एक मुख्य भूमिका है जबकि शराब के नियमित सेवन को घर–घर में पंहुचाने में एक मुख्य भूमिका रेड वाईन ने निभाई। जिन घरों में शराब का प्रवेश

वर्ष 1970 के बाद के दौर में लिवर के गंभीर मरीजों की संख्या में ब्रिटेन में 500 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है व इसमें शराब के बढ़ते चलन की एक मुख्य भूमिका है जबकि शराब के नियमित सेवन को घर-घर में पंहुचाने में एक मुख्य भूमिका रेड वाईन ने निभाई।

वर्जित था या बहुत सीमित था, वहां भी रेड वाईन ने प्रवेश पर लिया और स्वास्थ्य की क्षति व लत (एडिक्शन) की संभावना की दृष्टि से सबसे चिंताजनक बात यह हुई कि बहुत से लोगों ने रेड वाईन का बहुत अधिक सेवन प्रतिदिन करना आरंभ कर दिया।

इस प्रवृत्ति से बहुत से स्वास्थ्य विशेषज्ञ व स्वास्थ्य कार्यकर्ता चिंतित हुए व उनके सतत् प्रयासों में ही ब्रिटेन में वर्ष 2016 में नए दिशा–निर्देश जारी हो सके। इन नए गाईडलाईन की ओर विश्व स्तर पर ध्यान आकर्षित हुआ है और उम्मीद है कि विश्व के अनेक अन्य देशों पर भी असर होगा। इस तरह जो प्रवृत्ति कुछ विशेष तरह की शराबों को अधिक स्वीकार्यता दिलवाने और उनका तेज प्रसार करने की रही है, संभवतः अब उस पर कुछ हद तक रोक लग सकेगी। इधर पर्यावरण विशेषज्ञों ने बताया कि वाईन उत्पादन में खतरनाक रसायनों का तेज प्रसार व ग्रीन हाऊस गैसों का अधिक उत्सर्जन हुआ। इकनामिस्ट पत्रिका ने लिखा कि एक लिटर वाईन के उत्पादन में 960 लिटर पानी खर्च होता है।

2. भारत में नई चिंताजनक प्रवृत्तियां: विश्व स्तर पर शराब उद्योग व उपभोग की इन प्रवृत्तियों व दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए ही हम भारत में हाल में आ रहे बदलावों को ठीक से समझ सकेंगे। हिमाचल प्रदेश बहुत पौष्टिक फलों वाला राज्य है। हाल के समाचारों के अनुसार हिमाचल प्रदेश विपणन एवं प्रसंस्करण निगम (एच.पी. एस.सी.) ने दिल्ली की एक कंपनी से अनुबंध किया है कि वह हिमाचल प्रदेश के सेब, पल्म व बुरांस की वाइन को देश के सभी बड़े शहरों तक पहुंचाए। प्रथम चरण में कंपनी 25 हजार लीटर वाईन तैयार करेगी। समाचारों के अनुसार वाइन बनाने के लिए यह कंपनी एच.पी.एम.सी. की मशीनरी का उपयोग करेगी। (दैनिक जागरण प्रकाशित समाचार)

हालांकि एच.पी.एस.सी. पहले भी पोषक तत्त्वों से शराब तैयार कर रही थी, पर अब निजी कंपनी के अनुबंध होने से इस तरह का शराब उत्पादन तेजी से बढ़ने की संभावना है।

इस निर्णय को सही सिद्ध करने के लिए यह कहा जा रहा है कि वाईन स्वास्थ्य के लिए अथिक हानिकारक नहीं है व इसमें एल्कोहल की मात्रा कम होती है। पर यह प्रचार तथ्य आधारित नहीं है। सच्चाई तो यह है कि वाईन में एल्कोहल की मात्रा बीयर से कहीं अधिक है।

अब इसके आगे एक नई खबर आई है, चायपत्ती का उपयोग भी वाईन बनाने में होगा ताकि चाय जैसी सहज उपलब्धि के पेय को भी शराबनुमा बनाया जा सके। नवभारत टाईम्स में 1 मई को यह समाचार प्रकाशित हुआ है– "जल्द ही दुनिया वाइन के एक नए जायके से रूबरू होगी। इस खास वाईन को बनाने में हिमालय की मशहूर कांगड़ा टी के साथ ही फलों का भी इस्तेमाल किया गया है इस कारण इसे एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट करार दिया जा रहा है। एक खास टेस्ट और फ्लेवर वाली इस टी वाइन को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक ऐंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की पालमपुर स्थित इकाई – इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नॉलाजी (आईएचबीटी) के साइंटिस्ट डा. एच. पी. सिंह ने दुनिया में पहली बार बनाया है। इस वाइन में करीब 12 प्रतिशत अल्कोहल है और इसका टेस्ट परंपरागत वाइन से हटकर है।

"आईएचबीटी के डायेक्टर डा. संजय कुमार बताते हैं कि इस वाइन में भरपूर मात्रा में में पॉलीफनोल्स हैं। इनको बेहतरीन किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स में शुमार किया जाता है। डा. संजय का कहना है कि इस वाइन को बाजार में लाने के लिए तमिलनाडु की एक कंपनी के साथ करार किया गया है। इस करार के तहत सरकार को एकमुश्त राशि के अलावा सेल पर पांच प्रतिशत रॉयल्टी भी मिलेगी।"

इस समाचार का आकर्षक शीर्षक है "चाय में जब घोली जाए थोडी सी शराब, होगा नशा जो तैयार..."

इसके साथ एक टिप्पणी भी 'क्योंकि बढ़ रहे हैं शौकीन' शीर्षक के अंतर्गत दी गई है– "भारत में अभी वाइन के शौकीनों की तादाद ज्यादा नहीं है, लेकिन हाल के दौर में इसमें इजाफा देखा जा रहा है। इसकी वजह इसे सेफ ड्रिंक माना जाना है। कई स्टडीज वाइन को स्वास्थ्य के लिए एक बेहतरीन ड्रिंक करार देती हैं। माना जा रहा है कि टी वाइन की देश में भी काफी डिमांड रहेगी। अभी दुनिया में वाइन के कारोबार में फ्रांस का दबदबा है।"

इसमें बड़ी बात यह है कि सरकार का अपना विज्ञान का संस्थान इस खतरनाक प्रवृत्ति को आरंभ कर रहा है। सरकार को इस खतरनाक प्रवृत्ति पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। इससे पहले बहुत समाचार आते रहे हैं कि दूर–दूर के गांवों में भी शराब के ठेके निरंतर बहुत तेजी से खुलते जा रहे हैं।

इस साजिश का एक पक्ष यह है कि शराब की दुकान का लाईसेंस प्राप्त किए बिना भी फ्रूट वाईन व टी वाईन के नाम से शराब बेचने के कुप्रयास आरंभ हो सकते हैं जबकि प्रकाशित समाचारों में इनमें एल्कोहल की मात्रा काफी अधिक बताई गई है। इस तरह देश को शराब के नशे में डुबाने की एक साजिश चल रही है जिसे रोकना बहुत जरूरी है। ❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें : **http:// swadeshionline.in/**

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीध्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

इन्द्रदेव की अगवानी की तैयारी ज़रूरी

अग्निदेव ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति, मार्च शुरु में ही जारी कर दी थी। अप्रैल अंत में शुरु होने वाली गर्म हवाओं के शिमला जैसे ठण्डे शहर में मार्च अंत में ही प्रवेश कर जाने से विज्ञप्ति की पुष्टि भी हो गई थी कि इस बार गर्मियां, पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा गर्म लू लेकर आयेंगी। इन्द्र देवता की ताज़ा प्रेस विज्ञप्ति में लिखा है कि यदि 'ला नीनो' का उभार इसी तरह जारी रहा तो इस वर्ष का भारतीय मानसून, सामान्य रहेगा। हालांकि 'ला नीनो' के उभार में मई अंत से कमज़ोरी आने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा रहा। यदि ऐसा हुआ तो मानसून के सामान्य से काफी कम रहने से भी इंकार नहीं किया जा सकता। हमारे लोक विज्ञानियों ने कहा ही है – ''जै दिन जेठ चलै पुरवाई, तै दिन सावन धूल उड़ाई।''

फिलहाल, गौर फरमाने की बात यह है कि सामान्य मानसून का ताजा अनुमान तत्काल राहत देने वाला संदेश हो सकता है, लेकिन लगातार बढ़ता अतिवृष्टि और अनावृष्टि का सिलसिला नहीं। यह सिलसिला गवाह है कि अब मानसून के सामान्य होने की गारंटी छिन गई है। बारिश, पूरे चौमासे में बरकरार रहेगी या फिर चंद दिनों में पूरे चौमासे का पानी बरस जायेगा; वर्षा आने की आवृति चमक और धमक कब, कहां और कितनी होगी; यह दावा भी अब मुश्किल हो गया है। अब मानकर चलना चाहिए कि बादलों से बरसने वाले पानी के साथ ये अनिश्चितायें तो अब रहेंगी ही। अमेरिका की स्टेनफार्ड यूनिवर्सिटी द्वारा पिछले 60 साल के आंकड़ों के आधार पर प्रस्तुत शोध कह रहा है कि दक्षिण एशिया में बाढ़ और सूखे की तीव्रता लगातार बढ़ रही है। ताप और नमी में बदलाव के कारण ऐसा हो रहा है। बदलाव की यह आवृति ठोस और स्थाई है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव, भारत के मध्य क्षेत्र में होने की आशंका व्यक्त की गई है।

बुनियादी प्रश्न यह है कि ऐसे में हम आमजन करें तो करें क्या? आपदा प्रबंधन कानून–2005, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी

अमेरिका की स्टेनफार्ड यूनिवर्सिटी द्वारा पिछले 60 साल के आंकड़ों के आधार पर प्रस्तुत शोध कह रहा है कि दक्षिण एशिया में बाढ़ और सूखे की तीव्रता लगातार बढ़ रही है। ताप और नमी में बदलाव के कारण ऐसा हो रहा है। बदलाव की यह आवति ठोस और स्थाई है।

– **अरूण तिवारी**

कानून को लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का इंतज़ार करें; निर्देशों को लागू करने के शासकीय तौर–तरीकों पर बहस करें; बाढ–सुखाड़ के मानक, राहत को लेकर नेता–अफसर और बांधा–तटबंधों को कोसें, हमारे हिस्से का पानी सोख लेने के लिए शराब, शीतल पेय तथा बोतलबंद पानी की कपंनियों पर उंगली उठायें अथवा हालात से निबटने में अपनी भूमिका निभाने की दिशा में कदम बढ़ायें?

मिथक का टूटना जरूरी

सही जवाब जानने के लिए सबसे पहले इस मिथक का टूटना ज़रूरी है कि किसी अकेले किसी सरकार अथवा बाज़ार के बूते जल संकट का समाधान संभव है। दूसरा मिथक यह है कि वर्षा औसत से ज्यादा हो तो बाढ़ तथा औसत से कम हो तो सूखा लाती है। सत्य यह है कि वार्षिक वर्षा औसत के मामले में राजस्थान के ज़िला जैसलमेर का स्थान भारत में सबसे नीचे है और मेघालय केगांव मावसींरम का सबसे ऊंचा; बावजूद इसके क्रमशः जैसलमेर में न हर साल सूखा घोषित होता है और न मावसींरम में हर साल बाढ़। इसका तात्पर्य यह है कि जिस साल, जिस इलाके में वर्षा का जैसा औसत और जैसी आवृति हो, यदि हम उसके हिसाब से जीना सीख लें तो न हमें बाढ़ सतायेगी और सूखा।

कारण ही निवारण

एक अन्य सत्य यह है कि बाढ़ हमेशा नुकसानदेह नहीं होती। सामान्य बाढ़ नुकसान से ज्यादा तो नफा देती है। बाढ़, प्रदूषण का सफाया कर देती है; खेत को उपजाऊ मिट्टी से भर देती है। अगली फसल का उत्पादन दोगुना हो जाता है। बाढ़ नफे से ज्यादा नुकसान तभी करती है, जब अप्रत्याशित हो; एक घंटे में चार महीने की बारिश जाये; वेग अत्यंत तीव्र है; नदी पुराना रास्ता छोड़कर नये रास्ते पर निकल जाये; बाढ़ के पानी में ठोस मलबे की मात्रा काफी ज्यादा हो अथवा ज़रूरत से ज्यादा दिन ठहर जाये। बाढ़ के बढते वेग, अधिक ठहराव, अधिक मलबे और अधिक मारक होने के कारण भी कई हैं : नदी में गाद की अधिकता, तटबंध, नदी प्रवाह मार्ग तथा उसके जलग्रहण क्षेत्र के परंपरागत जलमार्गों में अवरोध। बांधों द्वारा बिना सूचना अचानक पानी छोड़ देने के कुप्रंबधन भी बाढ़ के मारक हो जाने का एक कारण है।

मिट्टी और इसकी नमी को अपनी बाजुओं में बांधकर रखने वाली घास व अन्य छोटी वनस्पति का अभाव, वनों का सफाया, वर्षा जल संचयन ढांचों की कमी, उनमें गाद की अधिकता तथा उनके पानी को रोककर रखने वाले पालों–बंधों का टूटा–फूटा अथवा कमजोर होना– ये ऐसे कारण हैं, जो बाढ़ और सुखाड़... दोनों का दुष्प्रभाव बढ़ा देते हैं। यदि खनन अनुशासित न हो; मवेशी न हों; मवेशियों के लिए चारा न हो; सूखे की भविष्यवाणी के बावजूद उससे बचाव की तैयारी न की गई हो, तो दुष्प्रभाव का बढना स्वाभाविक है; बढ़ेगा ही। ऐसी स्थिति में सूखा राहत के नाम पर खैरात बांटने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। उसमें भी बंदरबांट हो तो फिर आत्महत्यायें होती ही हैं। ऐसे अनुभवों से देश कई बार गुजर चुका है। गौर करने की बात है कि अकाल पूरे बुंदेलखंड में आया, लेकिन आत्महत्यायें वहीं हुईं, जहां खनन ने सारी सीमायें लांघी, जंगल का जमकर सफाया हुआ और मवेशी बिना चारा मरे; बांदा, महोबा और हमीरपुर।

आइये, सबसे पहले हम बारिश की हर बूंद को पकड़कर धरती के पेट में डालने की कोशिश तेज कर दें। परंपरागत तौर पर लोग यही करते थे। इसके लिए दो तारीखें तय थीं –कार्तिक में देवउठनी एकादशी और बैसाख में अक्षया तृतीया।

इंतज़ार बेकार, तैयारी जरूरी

निष्कर्ष स्पष्ट है कि यदि इंद्रदेव की विज्ञप्ति जारी कर दी है तो उसके संदेश को समझकर उनकी अगवानी की तैयारी करें। तैयारी सात मोर्चों पर करनी हैः पानी, अनाज, चारा, ईंधन, खेती, बाजार और सेहत। यदि हमारे पास प्रथम चार का अगले साल का पर्याप्त भंडारण है तो न किसी की ओर ताकने की ज़रूरत पडेगी और न ही आत्महत्या के हादसे होंगे। खेती, बाजार और सेहत ऐसे मोर्चे हैं, जिनके विषय में कुछ सावधानियां काफी होंगी।

तैयार रखें पानी के कटोरे

आइये, सबसे पहले हम बारिश की हर बूंद को पकड़कर धरती के पेट में डालने की कोशिश तेज कर दें। परंपरागत तौर पर लोग यही करते थे। इसके लिए दो तारीखें तय थीं –कार्तिक में देवउठनी एकादशी और बैसाख में अक्षया तृतीया। ये अबूझ मुहुर्त माने गये हैं। इन दो तारीखों को कोई भी शुभ कार्य बिना पंडित से पूछे भी किया जा सकता हैं। इन तारीखों में खेत भी खाली होते हैं और खेतिहर भी। ये हमारे पारंपरिक जल दिवस हैं। अतः गांव पानी के इंतजाम के लिए हर वर्ष दो काम अवश्य करता थाः देवउठनी एकादशी को नये जलढांचों का निर्माण और अक्षया तृतीया को पुराने ताल की मिट्टी निकालकर पाल पर डाल देना।

जवाबदेही निभाएं संस्थान

शराब, शीतल पेय और बोतलबंद पानी बेचने वाली कंपनियां, गांवों की

गरीब–गुरबा आबादी के हिस्से का पानी लूटकर मुनाफा कमाती हैं। इस लूट को रोकने हेतु ज़रूरी है कि हम उन्हे बाध्य करें कि वे जैसे और जितने पानी का दोहन करती हैं, कम से कम उतना और वैसी गुणवत्ता का पानी धरती को वापस लौटाएं। उपयोग किए पानी को पुर्नोपयोग लायक बनाकर, जलानुकूल हरीतिमा बढ़ाकर तथा वर्षा जल संचयन इकाइयों की साफ–सफाई, रखरखाव, नए ढांचों का निर्माण की जवाबदेही उठाकर वे ऐसा कर सकती हैं।

व्यापार में दो प्रतिशत मुनाफा से ज्यादा न कमाना और अपने मुनाफे का 10 प्रतिशत धर्मादे में लगाने का सिद्धांत, लाभ के साथ सभी के शुभ को जोड़कर चलने का भारतीय व्यापारिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत की पालना के कारण ही व्यापारियों को कभी महाजन यानी 'महान जन' कहा जाता था। जिन व्यापारियों को प्रकृति और भारतीयता के प्रति तनिक भी सम्मान है, उन्हे चाहिए कि वे फिर से महान जन बनने की पहल करें।

पानी के बाज़ार के खिलाफ एक औज़ार – प्याऊ

पानी के बाज़ार की बढ़ती लूट घटाने के लिए ऐसे उत्पादों की बिक्री को हतोत्साहित करना भी ज़रूरी है। शराब, बाज़ार आधारित शीतल पेय और बोतलबंद पानी का उपभोग कम करके भी हम इस लूट को घटा सकते हैं। शीतल पेय और बोतलबंद कंपनियों ने अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्थल से सार्वजनिक नल गायब दिए हैं। रेलवे स्टेशनों पर लगे 'वाटर प्वाइंट' की बिक्री बढ़ाने के लिए ट्रेन आने के समय पर प्लेटफॉर्म के नलों पर पानी बंद करने की कारगुजारी मैने खुद कई स्टेशनों पर देखी।

जरूरत भर भंडारण जरूरी

गेहूं की फसल कटकर घर पहुंच चुकी है। ऐसे खेतिहर परिवार जिनकी आजीविका पूरी तरह खेती पर ही निर्भर है, वे इनका इतना भंडारण अवश्य कर लें कि अगली रबी और खरीब... दोनों फसलें कमजोर हों, तो भी खाने के लिए बाज़ार से खरीदने की मजबूरी सामने न आये। यदि गलती से आप धान का घरेलु भंडार खाली कर चुके हों तो अतिरिक्त मोटे अनाज के बदले चावल ले लें; क्योंकि सूखा पड़ा तो चावल के दाम बढ़ेंगे।

जमाखोरी और कीमतों पर नियंत्रण

बाजार में जमाखोरी और कीमतों की बढोत्तरी को नियंत्रित करना तथा सरकारी स्तर पर भंडारण क्षमता व गुणवत्ता का विकास वर्तमान सरकार के समक्ष सबसे जरूरी व पहली चुनौती है। यह आसान नहीं है। यदि वह यह कर सकी तो बधाई का पात्र बनेगी; नहीं तो उसके खिलाफ उठती लहर को सैलाब बनते समय नहीं लगेगा।

भंडारण व प्रसंस्करण क्षमता का विस्तार

गौरतलब है कि भंडारण गृहों में 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और शीतगृहों में विशेष कर्ज व छूट योजनााओं के बावजूद कोई विशेष प्रगति देखने को नहीं मिल रही है। गोदामों में अनाजों की बर्बादी के नजारे आज भी आम हैं। भारत में सब्जी तथा फल उत्पादन की 40 प्रतिशत मात्रा महज् स्थानीय स्तर पर उचित भंडारण तथा प्रसंस्करण सुविधााओं के अभाव में नष्ट हो जाती है। इसका पुख्ता स्थानीय रोजगार व आर्थिक स्वावलंबन का विकास तो होगा ही, सूखे के नजरिये से भी इस मोर्चे पर पहल सार्थक होगी।

चारे और ईंधन का अतिरिक्त इंतजाम

सूखे का अन्य पहलू यह है कि सूखा पड़ने पर भूख और प्यास के कारण सबसे पहले मौत मवेशियों की होती है। पीने के पानी और चारे के इंतजाम से मवेशियों का जीवन का तो बचेगा ही, उनके दूध से हमारी पौष्टिकता की भी रक्षा होगी। इसी तरह ईंधन का पूर्व इंतजाम भी कम महत्वपूर्ण नहीं। कई ऐसे झाड़–झंखाड़, पत्ती व घास, जिन्हें हम बेकार समझकर अक्सर जलाया दिया करते हैं; उन्हे सुखाकर चारे और ईंधन के रूप में संजोने का काम अभी से शुरु कर दें।

समझदार करें फसल चक्र में बदलाव

इसी क्रम में एक जरूरी एहतियात खेती के संदर्भ में है। चेतावनी है कि वर्षा कम होगी। हो सकता है इतनी कम हो कि फसल ही सूख जाये या फूल–फल में बदलने से पहले ही मर जाये। क्या यह समझदारी नहीं कि ऐसे में मैं गन्ना–धान जैसी अधिक पानी वाली फसल की बजाय कम पानी वाली फसलों को प्राथमिकता दूं? मोटे अनाज, दलहन और तिलहन की फसलें बोएं?

इसके अलावा हमें चाहिए कि हम सब्जी, मसाले, फूल व औषधि आदि की खेती को तेज धूप से बचाने के लिए लिए पॉलीहाउस, ग्रीन हाउस आदि की सुविधा का लाभ लें। खेत में नमी बचाकर रखने के लिए जैविक खाद तथा मल्चिंग जैसे तौर–तरीकों का जमकर इस्तेमाल करें। कृषि, बागवानी, भूजल, भंडारण, प्रसंस्करण तथा गृह आदि विभागों को भी चाहिए कि संबंधित तैयारियों में जिम्मेदारी के साथ सहयोगी बने।

काम आयेगी सेहत में सतर्कता

सूखा पड़ने पर मौसम और मिट्टी की नमी में आई कमी सिर्फ खेती को ही चुनौती नहीं देती, हमारी सेहत को भी चुनौती देती है। अतः एहतियाती कदम उठाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अलावा सतर्क तो हमें भी होना ही पड़ेगा। भूलें नहीं कि दूरदृष्टि वाले लोग आपदा आने पर न चीखते हैं और न चिल्लाते हैं; बस! एक दीप जलाते हैं। समय पूर्व की तैयारी एक ऐसा ही दीप है। आइये, प्रज्जवलित करें। ❑❑

लोकमत परिष्कार-एक जन आंदोलन

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आज लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन जनता के लिए जनता के द्वारा। किन्तु जानकारी और जागरुकता के अभाव में जनता आज स्वयं को लाचार महसूस कर रही है। शासन तंत्र पर जनता की कोई पकड़ नहीं है। जबकि लोकतंत्र का निर्णायक तत्व लोकमत होता है। अतः हमें यदि वास्तविक लोकतंत्र अर्थात् जनता का शासन कायम करना है तो प्रत्येक मतदाता को जागरूक और संस्कारित करना होगा।

देश की वर्तमान दुर्दशा के लिए केवल राजनेताओं को दोष देने से समस्या का हल नही होगा। लोकतंत्र में मतदाता ही तय करता है कि शासन कौन चलाएगा। भ्रष्टाचार, जातिवाद, भेदभाव या सांप्रदायिकता फैलाने वाले नेताओं को अपना प्रतिनिधि चुनकर संसद या विधानसभा में कौन भेजता है? हम इस बात को लेकर कितने गंभीर हैं कि सांसद या विधायक का कार्य हमारे लिए कानून बनाना है? क्या वह उस कार्य को कर रहा है। आज तो संसद एवं विधान सभाओं का समय बर्बाद किया जा रहा है।

अतः जब तक प्रत्येक मतदाता को जागरूक और शिक्षित नहीं किया जाएगा तब तक उसे न तो अपने वोट की ताकत का अहसास होगा और न हमारी दुर्दशा का अंत। मतदाता को जानकार, जागरूक और जिम्मेदार बनाने की प्रक्रिया का ही नाम है लोकमत परिष्कार है।

क्यों जरुरी है लोकमत परिष्कार?

वर्तमान में देश में लगभग 50–60 प्रतिशत लोग ही मतदान करते हैं। ये मत अनेक प्रत्याशियों में बंट जाते हैं और मात्र 20–25 प्रतिशत मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति जनता का प्रतिनिधि मान लिया जाता है। इसे बहुमत का शासन कहना लोकतंत्र का मजाक नहीं तो और क्या है? वोट बैंक की कुत्सित राजनीति का कारण भी यही है। अवांछित लोग जेल में बंद रहते हुए भी जातिवाद या सांप्रदायिकता की भावना भड़काकर पैसे–शराब आदि बांट कर 10–12 प्रतिशत वोटों का जुगाड़ कर लें तो उनकी जीत पक्की हो जाती है। मतदाता

जब तक प्रत्येक मतदाता को जागरूक और शिक्षित नहीं किया जाएगा तब तक उसे न तो अपने वोट की ताकत का अहसास होगा और न हमारी दुर्दशा का अंत। मतदाता को जानकार, जागरूक और जिम्मेदार बनाने की प्रक्रिया का ही नाम है लोकमत परिष्कार है।

– डॉ. विजय कुमार वशिष्ठ

यदि इस रहस्य को समझ जाए तो इस तरह के अनैतिक हथकण्डों से चुनाव जीतने वालों के मंसूबों पर पानी फेरा जा सकता है।

कैसे होगा लोकमत परिष्कार?

- प्रत्येक मतदाता को यह बोध कराना होगा कि लोकतंत्र का अधिकारी मतदाता होता है। जाति, संप्रदाय, या पैसे के कारण वोट बैंक हिस्सा बनना जातिवाद, सांप्रदायिकता या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है।
- प्रत्येक मतदाता को अनिवार्य मतदान करना होगा।
- वर्तमान चुनाव पद्वति में परिवर्तन कर जीत के लिए वास्तविक बहुमत अर्थात 51 प्रतिशत मत प्राप्त करना सुनिश्चित करना होगा और इस सबके लिए यह विचार प्रत्येक मतदाता तक पहुँचाना होगा।

आज मतदाता अपने आप को लाचार महसूस करता है। वह सोचता है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं। मतदाता में यह विश्वास जगाना आवश्यक है कि लोकतंत्र में नियामक तत्व मैं हूं। लोकतंत्र में मतदाता शक्तिमान एवं संप्रभु होता है। हम जनप्रतिनिधि क्यों चुनते है? इसकी जानकारी प्रत्येक मतदाता को होनी चाहिए। हम कानून बनाने वालों का चुनाव करते हैं। हमारा प्रतिनिधि कैसा है? कौन है? उसका चरित्र एवं व्यवहार कैसा है? इसकी जानकारी भी मतदाताओं को चुनाव आयोग दुारा तथ्यात्मक रुप से उपलब्ध करायी जानी चाहिए। हमारे देश में 70 वर्षों से लोकतंत्र है। मतदाता परिपक्व भी है लेकिन आज भी मतदान का आधार संकीर्ण है, मतदान का प्रतिशत बहुत कम है। शिक्षित एंव सम्पन्न लोग मतदान करते ही नहीं हैं। अतः लोकमत परिष्कार का अभियान चलाने की आवाश्यकता है। इस संबंध में कुछ **चुनाव सुधार भी आवश्यक** हैः–

> **लोक जागृति के माध्यम से जनता का दबाव उत्पन्न करने की आवश्यकता है। आये लोकतंत्र को सांगोपांग बनाने के लिए हम एकजुट हों।**

1. मताधिकार को मूल–कर्तव्य बनाना (अनिवार्य मतदान)
2. प्रत्याशियों के बारे में तथ्यात्मक जानकारी चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध करवाना।
3. चुनाव प्रचार का व्यय सरकार द्वारा वहन करना
4. पंचायत से लेकर लोकसभा तक के चुनाव 5 वर्षों में एक साथ करवाना।
5. निर्वाचित प्रत्याशी के लिए 51 प्रतिशत मत प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाना।

लोकमत परिष्कार करेगा कौन?

यह बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इसका उपाय है, जन जागरण। प्रथमतः समाज में ओपीनियन मेकर को आगे आना होगा। इसके लिए छोटे–छोटे समूह में विचारगोष्ठी, सम्मेलन कार्यशाला आदि कार्यक्रमों का आयोजन करना होगा। इन कार्यक्रमों के लिए संक्षिप्त साहित्य का निर्माण करना होगा। नारे, बैनर, गीत, कविता, कार्टून आदि का उपयोग करना होगा। इस विषय में रूचि लेने वाले सभी विचार धाराओं के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर जन जागरण की आवश्यकता है। वर्तमान में राजस्थान पत्रिका ने यह बीड़ा उठाया है। मुझे विश्वास है कि यह आंदोलन प्रखर होगा तथा हमारे देश में लोकतंत्र का परिष्कार आवश्यक रूप से होगा।

सत्तालोलुप राजनेता इस कार्य को नहीं होने देना चाहेंगे। यदि ऐसा कोई आंदोलन चलता है तो शायद वे अवरोध भी उत्पन्न करेंगे। अतः लोक जागृति के माध्यम से जनता का दबाव उत्पन्न करने की आवश्यकता है। आये लोकतंत्र को सांगोपांग बनाने के लिए हम एकजुट हों। इसके लिए देश में एक बार फिर जन आंदोलन करने की आवश्यकता है – जो समय की मांग है। इस कार्य को हम सब मिलकर कर सकते हैं। ❑❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

समग्र शिक्षा नीति की ओर-निर्णायक कदम

(भाग–1)

आज़ादी के 70 वर्षों से भारत में स्थायी शिक्षानीति का निर्धारण नहीं हो सका है क्योंकि अनेक विसंगतियों एवं विरोधाभासों के चलते कुछ नीतियाँ देश के सभी शिक्षण संस्थानों में समान रूप से लागू नहीं हो पाती है। शिक्षा का श्रेणीगत (निजी व सरकारी) विभाजन शिक्षा के स्तर को उच्च और निम्न स्तर में बाँट देता है, भाषागत विभाजन सांस्कृतिक विभेद पैदा करता है, वहीं जातिगत विभाजन राजनीतिक स्तर पर सामाजिक वर्गीकरण कर देता है। इस तरह शिक्षा के मूल उद्देश्यों की क्रियान्विति से प्रबंधन और प्रशासन दोनों भटक जाते हैं।

शासन द्वारा मानव संसाधन विकास (HRD) मंत्रालय द्वारा शिक्षा नीति तय करने के लिये जो समिति तय की जाती है, उसमें भी राजनीतिक व जातिगत समीकरण, आर्थिक लाभ के लिये कॉरपोरेट सेक्टर व निजी प्रक्रमों की दखलदांजी समुदाय विशेष को प्राथमिकता, दक्षिण भारत का भाषायी संकट जैसे कई प्रकार के विभेद प्रकट होते हैं। निर्धारित समिति में IAS, सांइटिस्ट, वाइस चांसलर, काउसिंल के अध्यक्ष और भूतपूर्व सदस्य होते हैं, जो वर्तमान में शिक्षा से किसी प्रकार जुड़े नहीं होते और शिक्षा की बुनियादी समस्याओं एवं आवश्यकताओं से पूर्णतया अनभिज्ञ होते हैं। शिक्षा नीति में विद्यार्थी और शिक्षक से लेकर प्रबंधक और प्रशासन तक किसी प्रकार का तालमेल स्थापित नहीं हो पाता। ये सदस्य अत्यंत उच्च श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा समाज के हित की अपेक्षा अपने व्यक्तिगत स्वार्थों और निजी प्रतिष्ठा को प्रभावी बनाने के लिये प्रयत्नशील रहते हैं।

शिक्षा के सभी स्तरों पर वर्षों से ढोयी जा रही मैकॉले पद्धति को जड़–मूल से नष्ट करने की जरूरत है इसलिये समुचित शिक्षा नीति में सुधार भारत के सुदढ़ भविष्य के लिये निर्णायक सिद्ध होंगे।

– डॉ. रेखा भट्ट

प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर विद्यार्थी की आवश्यकताएं और शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्यों में बहुत अंतर होता है। किन्तु मूल रूप से शिक्षा के सभी स्तरों पर वर्षों से ढोयी जा रही मैकॉले पद्धति को जड़–मूल से नष्ट करने की जरूरत है इसलिये समुचित शिक्षा नीति में सुधार भारत के सुदढ़ भविष्य के लिये निर्णायक सिद्ध होंगे। मैकॉलयी पद्धति के अनुसार अंकों के आधार पर मूल्यांकन के स्थान पर डिग्री में विद्यार्थी की उपलब्धियों, प्रतिभा और योग्यता का मूल्यांकन प्रदर्शित किया जाये तो वह डिग्री विद्यार्थी को सीधे रोजगार प्राप्ति से जोड़ेगी।

अंक प्रणाली समाप्त करने से कई सामाजिक समस्याएं जो शिक्षा को विकृत करती जा रही हैं वे स्वतः समाप्त हो जाएंगी। पहली– प्रश्न पत्र लीक होने जैसी समस्या जो पहले कभी–कभार आती थी। तकनीकी साधनों के विकसित होने के साथ सभी प्रतियोगी एवं डिग्री परीक्षाओं में यह समस्या बढ़ती जा रही है। सबसे विश्वसनीय माने जाने वाले CBSE बोर्ड की 12वीं के प्रश्नपत्र लीक होने की घटना को HRD द्वारा गंभीरता से लिया जाना चाहिये। दूसरी बड़ी समस्या है सामूहिक नकल। नकल के लिये ब्लूटूथ आदि गैजेट्स का उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। बिहार में विद्यालय की खिड़कियों से नकल कराते हुए दृश्य अब सभी जगह आम होते जा रहे हैं। तीसरी समस्या है, फर्जी डिग्रियों का कारोबार। विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में पात्रता प्राप्त करने के लिये बड़ी कीमत चुकाकर

निजी विश्वविद्यालयों से नकली डिग्री प्राप्त कर लेता है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक ही निजी विश्वविद्यालय के छात्रों को बहुतायत में पात्रता मिलने से जाँच की गई। पुष्टि होने से निजी क्षेत्र से प्राप्त डिग्रियों की मान्यता भी अब संदिग्ध ा मानी जाने लगी है। इसी तरह चौथी समस्या पास बुक्स माफिया की है। न्यूनतम अंक प्राप्त कर पास होने और स्नातक, स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त करने के लिये विद्यार्थी पाठ्यपुस्तकों के स्थान पर कई तरह की पास–बुक्स का प्रयोग करते हैं क्योंकि डिग्री विद्यार्थी की प्रतियोगी परीक्षा में पात्रता तो सुनिश्चित करती है किंतु उनके रोजगार को नहीं। पांचवीं समस्या आरक्षण की है। भारतीय शिक्षण तंत्र में जीवन को ऊपर उठाने के उद्देश्य से दी जाने वाली शिक्षा मानवीय मूल्यों पर आधारित थी। आज इसी शिक्षा प्रणाली ने विद्यार्थी के जीवन का अंतिम लक्ष्य अंक प्राप्ति बना दिया है। डिग्री में व्यक्तिगत योग्यता को मूल्यांकन का आध ाार बनाने से शिक्षण संस्थानों में अंकों के आधार पर दिये जाने वाले आरक्षण का औचित्य समाप्त हो जायेगा।

किसी भी परीक्षा परिणाम के लिये शिक्षण संस्थान विद्यार्थी की अपेक्षा शिक्षक की जवाबदेही सुनिश्चित करें तो शिक्षक की भूमिका अर्थपूर्ण बनेगी। शिक्षक द्वारा सार्थक शिक्षण दिया जाना ही शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाता है। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर शिक्षण सुचारू नहीं होने के भिन्न–2 कारण सामने आये हैं। प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों द्वारा कराये जाने वाले अतिरिक्त कार्य जैसे पोषाहार योजना, पल्स पोलियो ड्रॉप्स का वितरण, जनसंख्या गणना, मतदान आदि कार्य सौंपे जाना उन्हें मूल शिक्षण कार्य से विमुख करता है। उच्च माध्यमिक कक्षाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं एवं नियमित पाठ्यक्रम के विस्तृत होने के कारण अतिरिक्त समय में ट्यूशन या कोचिंग देकर अपने निर्देशन में पूरा पाठ्यक्रम करवाते हैं। उच्च शिक्षा में शिक्षक को API (Academic Performance Indicator) स्कोर को पूरा करना होता है इसके लिये शोध छात्रों की संख्या, शोध पत्रों की संख्या, शोध पत्र पढ़ने व भाग लिये गये क्रॉन्फ्रेस, सेमिनार की संख्या, प्रकाशित पुस्तकों की संख्या आदि मानदण्डों को पूरा करना होता हैं। अतः उच्च शिक्षा में शोध कार्य को प्राथमिकता से पूरा किया जाता है और शिक्षण कार्य उपेक्षित ही रहता है।

शिक्षकों को शिक्षण प्रशिक्षण देकर शासन द्वारा औपचारिकता पूर्ण कर ली जाती है। शिक्षण प्रशिक्षण पर बड़ी राशि व्यय की जाती है। पाठ्यक्रम में शिक्षक का दायित्वपूर्ण करने के लिये इस प्रकार निर्देशित किया जाये, कि वह कक्षा में नवाचार लाने का प्रयास करें, आधुनिक तकनीक के माध्यमों का उपयोग कर अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का प्रयास करे, स्वयं नया जानने व विद्यार्थी की आवश्यकताओं के अनुसार प्राचीन देशी–विदेशी अवधारणाओं व अन्वेषण के आधार पर नये अन्वेषण करने के लिये प्रेरित करे। मॉडल, चार्ट, डिस्प्ले, आदि द्वारा शिक्षण को रूचिकर बनाये तथा विद्यार्थी को अपने साथ शिक्षण से जोड़ने का प्रयास करें।

प्राथमिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रणाली की नींव होती है, ये ही बच्चे देश के भविष्य का निर्माण करते हैं। प्रारम्भिक शिक्षण अवस्था में बच्चे सबसे अधिक संवेदनशील होते है।

प्रत्येक स्तर की शिक्षा के उद्देश्यों को प्रधानता देकर पाठ्यक्रम की विषय वस्तु तय करें। इस तरह से पाठ्यक्रमों पर आधारित पाठ्यपुस्तकें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिये उपयोगी सिद्ध होंगी और कक्षा–कक्ष में पूर्ण मनोयोग से अध्ययन हो सकेगा।

कक्षा–कक्ष में क्रियात्मक, प्रयोगात्मक एवं रचनात्मक तरीकों से शिक्षण प्रदान करने से विद्यार्थी भी शिक्षण में भागीदार बनते हैं। वर्तमान स्थिति में विज्ञान जैसे प्रयोगधर्मी विषय भी प्रयोगाशाला, कार्यशाला व संसाधनों के अभाव में निष्क्रिय व नीरस बन गये हैं। शिक्षा नीति में, शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर विद्यार्थी की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण पद्धति तय की जाये, तो उचित पाठ्यक्रम का निर्धारण हो सकेगा और पाठ्यपुस्तकें प्रासंगिक होगी तथा शिक्षक द्वारा किया जाने वाला सार्थक शिक्षण विद्यार्थी की योग्यता और उसकी क्षमता बढ़ायेगा।

प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 5वीं तक) संपूर्ण शिक्षा प्रणाली की नींव होती है, ये ही बच्चे देश के भविष्य का निर्माण करते हैं। प्रारम्भिक शिक्षण अवस्था में बच्चे सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं इस समय उनमें अधिक से अधिक ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता होती है। बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास की प्रक्रिया में स्वतंत्र, खुशनुमा, सकारात्मक वातावरण सहायक होता है। परीक्षा का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा निर्मित कर बच्चों के लिये शिक्षा को तनावपूर्ण बनाता है और माता–पिता भी बच्चों पर अच्छे प्रदर्शन का दबाव बनाते हैं। प्रारम्भिक शिक्षा में विद्यार्थी परिवार और समाज में अपनी पहचान स्थापित करना शुरू करता है, इस स्थिति में कैरियर की चिंता की अपेक्षा उसे अपने परिवार, समाज और आस–पास के वातावरण को देखने समझने का अवसर देने की आवश्यकता होती है जिससे वह अपने दायित्वों का निर्धारण कर सके। प्रकृति के बीच रह कर पर्यावरण संरक्षण का महत्त्व जाने

और आगे चलकर पर्यावरण संरक्षण के लिये प्रतिबद्ध रहे। कक्षा से बाहर बच्चे अधिक सीखते हैं, अतः उनके लिये खेलकूद, भ्रमण, सांस्कृकि व साहित्यिक गतिविधियों से शिक्षण को सक्रिय एवं गतिशील बनाया जा सकता है। सामूहिक रूप से खेल–खेल में शिक्षण करवाने से बच्चे की अभिव्यक्ति क्षमता और अभिरूचियाँ प्रकट होंगी। नियत पाठ्यपुस्तकों की अपेक्षा वे रंग–बिरंगे प्रॉप्स, कार्ड्स, कटआउट्स, स्केचेज़, विडियो आदि की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। प्राचीन गुरूकुल पद्धति के अनुरूप मुखाग्र वाचिक पद्धति द्वारा ज्ञान को कण्ठस्थ करना लाभ दायक होता है, यह सभी विकसित देशों में भी अनुसंधान द्वारा सिद्ध किया जा चुका है। भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत कविताएँ, गीत, प्रेरणास्पद कहानियाँ, इतिहास के महापुरूषों की जीवनियों, ऐतिहासिक स्थलों, महान वैज्ञानिकों के अन्वेषण के बारे में जानने से उनके भावी जीवन को नैतिक व आध्यात्मिक आधार मिलेगा और भविष्य के लिये अनुसंधान की मनोवृत्ति बनेगी।

शिक्षण के अतिरिक्त पोषाहार आदि कार्यों के लिये शिक्षकों की अपेक्षा बेरोजगार युवाओं की वर्कफोर्स तैयार करने से उन्हें आर्थिक सहायता एवं सामाजिक कार्यों में संलग्न होने के अवसर मिलेंगे। प्राथमिक स्तर पर अंकों की परीक्षा प्रणाली समाप्त कर दी जाये किन्तु मूल्यांकन पद्धति को यथावत् रखा जाये जिसमें प्रत्येक वर्ष बच्चों द्वारा प्राप्त ज्ञान में वृद्धि का मूल्यांकन हो। बच्चों का भारत व दुनिया की संस्कृति इतिहास, विज्ञान व साहित्य का ज्ञान बढ़े। उनके संस्कारों को परिष्कृत कर प्रभावशाली व्यक्तित्व का गठन हो। उनकी प्रतिभा और योग्यता के मूल्यांकन द्वारा उनकी भावी शिक्षा की दिशा तय की जा सके।

अभी तक चली आ रही अंकों पर आधारित परीक्षा प्रणाली के हटाये जाने से प्राथमिक शिक्षण में शिथिलता न आये, जिस तरह '8वीं तक पास करने के नियम' के कारण आई थी। HRD द्वारा नई शिक्षा नीति में प्राथमिक स्तर पर प्रशासन द्वारा स्थानीय नियामक तंत्र बनाना होगा। यह तंत्र विद्यालय प्रबंधक द्वारा अध्यापन की समुचित व्यवस्थाओं और नीति के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करें। विद्यार्थी व अभिभावकों के फीडबैक द्वारा शिक्षा के अनुकूल वातावरण बनाये जाने के लिये संस्था–प्रधानों को जवाबदेह बनाया जाये। उन्हें विशेष अधिकार प्रदान किये जायें जो बच्चों को प्रताड़ना व शोषण से बचा सकें और शिक्षकों को शिक्षण कार्य के प्रति समर्पित कर सकें। विद्यालय में बच्चों को सुरक्षित एवं विकसित होने का वातावरण देने से बच्चों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने पर भी उतना ही गर्व होगा जितना निजी में होता है और विद्या के मन्दिरों की विश्वसनीयता लौटेगी।

माध्यमिक शिक्षण काल (कक्षा 6 से 8वीं) विद्यार्थी की कला, साहित्य, कौशल आदि अभिरूचियों को भविष्य में विकसित करने का आधार होता है। अतः पाठ्यचर्या में कौशल, व्यवसाय, कलात्मक, रचनात्मक अभिरूचियों के विविध क्षेत्रों को समाहित किया जाना चाहिये। अभिरूचियों को विकसित करने के लिये उनसे जुड़ी प्रारम्भिक जानकारी, प्राचीन अवधारणाएँ, उपलब्धियाँ तथा इससे जुड़ी समस्याओं और भविष्य की संभावनाओं का सामूहिक शिक्षण दिया जा सकता है। डिजीटल एवं विडियो डिसप्ले, प्रयोगशालाओं में तथा कार्यशालाओं में प्रशिक्षण और संगोष्ठी, सेमिनारों में प्रतिभागिता द्वारा कार्य की विवेचना करने से, सोचने विचारने और करने से कार्य की विधि विकसित होगी और विद्यार्थी के कार्य करने का अनुभव बढ़ेगा। नये विचारों के विकल्प सामने आएंगे। विद्यार्थी की जिज्ञासा बढ़ाने, प्रश्न पूछने, समाधान देने के लिये शिक्षक उन्हें प्रोत्साहित करें, उन्हें रोकने से उनमें नया करने का हौंसला व सृजनशीलता समाप्त हो जाती है। शिक्षक भी बच्चों के विकास के लिये दी गई गतिविधियों में संलग्न हो, निरंतर अभ्यास द्वारा उन्हें अपने–अपने क्षेत्र में विकसित करने का प्रयास करें, इससे शिक्षण की क्रियाशीलता और व्यवहारिकता बढ़ेगी। यह शिक्षण विद्यार्थी के उच्च माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश करते समय विषय के चयन को सहज बनायेगा। योग्य नागरिक बनने की दिशा में विद्यार्थी दृढ़ता और विश्वास के साथ उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिये उन्मुख होगा। भारत में प्राचीन काल से पारिवारिक उद्योगों और व्यवसायों को आगे बढ़ाने की परंपरा रही है। आज भी ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहने वाले या गांवों से शहरों की ओर पलायन कर चुके परिवारों के विद्यार्थी पारिवारिक आय में योगदान के लिये लघु एवं कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, कृषि व्यवसाय एवं अन्य उद्यमिता से जुड़े कार्यों को आजीविका का माध्यम बनाना चाहते हैं। शिक्षा में तेजी से बढ़ते वैश्विकरण व तकनीकी विकास के साथ इन परंपरागत उद्यमों का संवर्धन होगा। उत्पादों की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ने से शिक्षा की गुणात्मकता बढ़ेगी। विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा से पहले ही ड्रॉप आउट नहीं करेंगे।

इस प्रक्रिया में आंकिक व संख्यात्मक मूल्यांकन करने की अपेक्षा विद्यार्थी के सीखने की व जानने की तत्परता, समझ बढ़ाने और नया करने की आतुरता, कल्पनाशीलता व सृजनशीलता जैसे गुणात्मक विश्लेषण का मूल्यांकन उचित होगा। विद्यार्थी को कला, साहित्य, प्रबंधन, उद्यमिता, व्यवसाय, कौशल आदि विषयों में अपनी प्रतिभा प्रकट करने व योग्यता विकसित करने के अवसर देना उन्हें उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर करने का महत्वपूर्ण कदम होगा।

(जारी...)

राष्ट्रीय परिषद बैठक

अहमदाबाद, गुजरात (5–6 मई 2018)

प्रस्ताव–1

विकास नीति बदलने की जरूरत

वर्तमान और पूर्व की सरकारों का हमेशा यह दावा रहा है कि पिछले 27 वर्षों में अपनायी गई नई आर्थिक नीति के कारण जीडीपी ग्रोथ में भारी वृद्धि हुई है। नीति निर्माताओं का यह कहना है कि जीडीपी ग्रोथ से ही नवीन प्रौद्योगिकी का विकास होता है, रोजगार बढ़ता है और लोगों का जीवन स्तर सुधरता है। लेकिन उनके दावे गलत सिद्ध हो रहे हैं। उत्पादन बढ़ने के नाम पर विलासिता की वस्तुओं और अमीरों के उपभोग की सेवाओं का ही उत्पादन बढ़ रहा है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थामस पिकेटी का शोध बताता है कि पछले 354 वर्षों की जीडीपी ग्रोथ का 66 प्रतिशत हिस्सा ऊपरी 10 प्रतिशत लोगों द्वारा हथिया लिया गया और 29 प्रतिशत ऊपरी 1 प्रतिशत द्वारा। रोजगार निर्माण इसका सबसे बड़ा शिकार है। ओईसीडी का कहना है कि भारत में 15 से 29 वर्ष आयुवर्ग के 31 प्रतिशत युवा न तो शिक्षा या प्रशिक्षण में है और न ही रोजगार में है। यानि बेरोजगार हैं। यही नहीं, जीडीपी ग्रोथ के प्रति झुकाव के कारण पर्यावरण ही नहीं सांस्कृतिक मूल्यों के ह्रास के प्रति भी सरकारों की संवेदनशीलता समाप्त हो रही है। पर्यावरणीय असंतुलनों से मानव मात्र का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है।

पिछले कुछ समय में सरकार के द्वारा कौशल निर्माण, स्टार्ट–अप, मुद्रा योजना सहित अनेक प्रयासों से रोजगार के अवसर बढ़ाने की कोशिश हुई है, लेकिन बेरोजगारी आज भी एक भीषण समस्या बनी हुई है। इसका कारण यह है कि भूमंडलीकरण के युग में विकास का मॉडल, रोजगारविहीन मॉडल बनकर रह गया है। बढ़ता विदेशी आयात और उसके कारण बड़ा व्यापार घाटा, देश से रोजगार को दूसरे देशों में भेजने का साधन मात्र बनकर रहा गया है। विदेशी मुद्रा की कमी की भरपाई विदेशी निवेश से की जा रही है, जिसके कारण देश के संसाधनों पर भी विदेशी काबिज होते जा रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जितना रोजगार निर्माण हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा रोजगार के अवसर वे नष्ट कर रहे हैं। उधर 'आर्टिफिशल इंटेलिजेंस' और अंधाधुंध मशीनीकरण के चलते और अधिक रोजगार नष्ट हो रहे हैं।

स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय परिषद की स्पष्ट मान्यता है कि यदि यह नीति जारी रही तो रोजगार सृजन नहीं हो पायेगा। एक ऐसी विकास की नीति बने, जिसमें जीडीपी ग्रोथ में उत्पादन में वृद्धि के साथ रोजगार में वृद्धि और विकेंद्रीकरण निहित हो। जहां लघु उद्यम काम कर सकते हैं, बड़े उद्योगों का प्रवेश वहां वर्जित हो। यानि एक बार फिर से लघु उद्योगों के लिए उत्पाद आरक्षित किये जायें और साथ ही साथ नीतिगत हस्तक्षेप के साथ लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाये। उद्योगों में रोजगार निर्माण के लिए सरकारी मदद मिले, ताकि लोग बिना कारण मशीनीकरण की ओर न बढ़ें। कौशल निर्माण के कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए उद्योगों के लिए आवश्यक कौशल निर्माण का विकास किया जाये। सरकार द्वारा रोजगार बढ़ाने हेतु कर्मचारी भविष्य निधि में सहयोग की योजना का स्वदेशी जागरण मंच स्वागत करता है।

देश में ऐसे विशेषज्ञों की कमी नहीं जो पश्चिम के इस विचार से अभीभूत हैं कि गांवों में रोजगार नहीं बढ़ाया जा सकता और इसलिए लोगों को गांव और कृषि से बाहर किया जाना चाहिए। नीति निर्माता, जो लगभग इन विशेषज्ञों से सहमत हैं, वे गांव और किसान की हालत को सुधारने हेतु अपेक्षित प्रयास नहीं करते। परिणाम यह है कि कर्ज में डूबे लाखों किसान आत्महत्या कर चुके हैं और यह क्रम थम ही नहीं रहा। हर बार किसानों की ऋण माफी, कृषि समस्या का हलमान लिया जाता है। कृषि में घटते रोजगार के कारण 'मनरेगा' पर खर्च बढ़ता जाता है। स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय परिषद यह मांग करती है कि देश की सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु अपेक्षित प्रयास करें। दाल, तिलहन, फल–फूल, सब्जी, खुंभ, बांस और अन्य लाभकारी फसलों, जिनमें रोजगार निर्माण की अधिक संभावनायें है, को बढ़ावा दिया जाये। खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी एव मुर्गी पालन, मछली पालन सहित गैर–कृषि कार्यों को प्रोत्साहन देकर अपार मात्रा में रोजगार के अवसर बढ़ाये जा सकते हैं, उसके लिए प्रयास हों।

बांस को वनोत्पाद की श्रेणी से अलग करने, मछली पालन और डेयरी में संलग्न लोगों (चाहे वे भूमिहीन भी हों) को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के फैसलों का स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय परिषद स्वागत करती है। साथ ही साथ मांग करती है कि डेयरी, मछली पालन, मशरूम उत्पादन, मुर्गी पालन, आदि को भी कृषि की श्रेणी में रखकर उन्हें रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाया जाये। साथ ही आग्रह करती है कि उपरोक्त सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन के रास्ते में आने वाली कठिनाईयों को दूर किया जाये। ❑

प्रस्ताव–2

स्वास्थ्य को सर्वसुलभकारी बनाया जाए

2014 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने उद्घाटित किया कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत में स्वास्थ्य पर प्रतिव्यक्ति निजी खर्च दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसममें से प्रमुख हिस्सा 68 से 72 प्रतिशत दवाओं पर खर्च किया जा रहा है। स्वदेशी जागरण मंच का मानना है कि अधिकांश योजनाएं एवं गतिविधियां जो भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई, वे 'स्वास्थ्य रक्षा' के स्थान पर 'चिकित्सा रक्षा' पर केंद्रित है। अधिक ध्यान एवं प्रयास अस्पताल खोलने और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की ओर है, जो अच्छा ही है। किंतु 'स्वास्थ्य सुरक्षा' की चेतना के प्रति बराबर ध्यान दिया जाना भी उतना ही आवश्यक है।

यह भी ध्यान में आता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना में 'आयुष' एवं अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों की अपेक्षा एलोपैथी उपचार पर अधिक बल दिया जाता है। स्वदेशी जागरण मंच यह मानता है कि आयुष–आयुर्वेद सिद्ध एवं यूनानी जैसी सुलभ एवं कम खर्चीली चिकित्सा पद्धतियों की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। आयुष योजना को शोध हेतु अधिक वित्तीय सहयोग दिया जाना चाहिए। आयुर्वेदिक चिकित्सकों की संख्या, वनौषधियों की उपलब्धता और अन्य अनुपूरक साधनों को बढ़ाने हेतु सहायता दिये जाने की आवश्यकता है।

स्वदेशी जागरण मंच सरकारी योजना के अंतर्गत जन–औषधी भंडार जिनके माध्यम से सस्ती सुलभ कीमतों पर दवा वितरण के प्रयास की सराहना करता है। यद्यपि यह सुविधा आकार और विस्तार में मांग की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है।

स्वदेशी जागरण मंच अनुभव करता है कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य नियंत्रण मंडल (एनपीपीए) जो कि अपरिहार्य दवाओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए महत्वपूर्ण घटक है, जिसे निरंतर निहित स्वार्थों के अंतर्गत कमजोर एवं निष्प्रभावी बनाने के लिए योजनाबद्ध प्रयास किये जा रहे है। वस्तुतः इससे उलट और अधिक आवश्यक दवाओं एवं चिकित्सा सहायक उपकरणों को एनपीपीए के नियंत्रण में लाने की आवश्यकता है। आवश्यक दवाओं के मूल्य नियंत्रण में बाजार आधारित मूल्य निर्धारण निष्प्रभावी रहा है। अतः 'लागत आधारित मूल्य सिद्धांत' पर वापस लौटने की आवश्यकता है। अत्यावश्यक दवाओं के मूल्य निर्धारण में बाजारकीय अवधारणा व्यावहारिक एवं युक्तियुक्त नहीं है।

स्वदेशी जागरण मंच का यह भी मानना है कि निहित स्वार्थ न केवल स्वास्थ्य योजना निर्माण में अनावश्यक दखल दे रहे हैं, वरन् चिकित्सकों के माध्यम से उनके हित साधन की दवाओं की पर्ची लिखवाने तक प्रभावी हैं। बिल मेलिंडा गेटस फाउंडेशन को स्वदेशी जागरण मंच द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया है, जिस पर सरकार द्वारा और ज्यादा कार्यवाही की जरूरत है।

स्वदेशी जागरण मंच केंद्र सरकार द्वारा लागू राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना का स्वागत करता है, जहां प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य रक्षा का क्रियान्वयन किया जाना है। प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में सुविधाएं एवं क्षमताएं बढ़ाने का प्रस्ताव एक अच्छा कदम है। यद्यपि जन–स्वास्थ्य, घर एवं शासकीय अस्पतालों की विकसित केंद्रों से प्रतिस्पर्धा अच्छा कदम नहीं है। इसी प्रकार उच्च्य गुणवत्तायुक्त तृतीयक स्तर पर निजी क्षेत्र को अनुमति देना, गंभीर रोगों में अत्यंत खर्चीली उपचार पद्धति को प्रश्रय देगा।

स्वदेशी जागरण मंच भारत सरकार द्वारा जारी आयुष्मान भारत योजना की सराहना करता है, जिसमें 50 करोड़ लाभार्थी द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ बीमा योजना द्वारा अनुमानित है। स्वदेशी जागरण मंच सरकार की राष्ट्रीय परिषद सरकार आगाह करती है कि इस अभियान में विदेशी बीमा कंपनियों, जो शुद्ध लाभ कमाने के उद्देश्य से भारत में कार्यरत है, उन्हें प्रवेश न दे।

स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय परिषद मांग करती है कि –

1. वृहत स्तर पर रोग निवारण पेयजल उपलब्धता, शिशुओं के लिये पोषक आहार, ग्राम स्तर पर स्वच्छता आदि स्वास्थ्य सुरक्षा निवारण हेतु योजनाएं बनाकर लागू करें।
2. उपचार के 'आयुष' तंत्र को आगे बढ़ाए, आयुष चिकित्सकों की उपलब्धता हो, जड़ी–बूटियों, वनोषधियों की खेती हो, उन्हें स्तरीय मानकों के अनुरूप बनाया जाये।
3. राष्ट्रीय औषध मूल्य नियंत्रण (एनपीपीए) को सक्षम किया जाए। उसकी शक्तियों को अत्यावश्यक दवाओं और उपकरणों के क्षेत्र में कम न किया जाए। लागत आधारित विधि मूल्य निर्धारण के लिए लागू की जाए, न कि बाजार आधारित मूल्य विधि।
4. स्वास्थ्य योजनाओं संबंधी गतिविधियों में विदेशी उपक्रमों की निहित स्वार्थ के साथ दखलअंदाजी तुरंत समाप्त की जाए।
5. जन–स्वास्थ्य सुरक्षा को निजी क्षेत्र एवं बीमा कंपनियों के हाथों में न छोड़ा जाए। ❑

प्रस्ताव–3

घरेलू अर्थव्यवस्था को बचाओ

अमरीका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शासन सूत्र संभालने के बाद दुनिया में संरक्षणवाद की लहर आ गई है और उसे व्यापार युद्ध का नाम दिया जा रहा है। सामान्यतः इसे अमरीका और चीन के बीच व्यापार युद्ध के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन यह साथ ही साथ विश्व व्यापार संगठन को चुनौती भी दे रहा है। विश्व व्यापार संगठन में शामिल सभी 168 देश समझौतों की शर्तों से बंधे हुए है। उनके पास कानूनन कोई अधिकार नहीं कि वे विश्व व्यापार संगठन समझौतों से इतर कोई एकतरफा फैसला ले सकें। पिछले 23 वर्षों से सदस्य देश दूसरे देशों के साथ व्यापार को बढ़ाने हेतु लगातार आयात शुल्क घटा रहे हैं और साथ गैर शुल्क बाधायें भी हटा रहे हैं। भारत को कई वस्तुओं पर आयात शुल्क जो 400 प्रतिशत या कई बार उससे भी अधिक था, घटाकर शून्य प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक करना पड़ा। साथ ही साथ 1400 वस्तुओं पर मात्रात्मक नियंत्रण भी समाप्त करने पडें।

विश्व व्यापार संगठन में विवाद निपटारण व्यवस्था भी है, जिसके अनुसार यदि कोई सदस्य देश दूसरे देश के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है, यदि वे उनके उत्पादों के खिलाफ आयात शुल्क या अन्य बाधायें खड़ी करें। सरकारी सब्सिड़ी, विशाल उत्पादन के कारण कम उत्पादन लागत, वित्त की कम लागत और सस्ते श्रम के कारण चीनी माल ने पिछले 15 वर्षों में दुनिया भर के बाजारों पर कब्जा कर लिया है।

दुनिया भर के इलैक्ट्रोनिक्स एवं टेलीकॉम उपकरण, उर्वरक, रसायन और दवा समेत सभी उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और भारत कोई अपवाद नहीं है। अमरीका और यूरोप के उद्योग बीमार हुए और वहां बेरोजगारी भी बढ़ी।

अमरीका के राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के नाते डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह वचन दिया था कि वो अमरीका में मैन्यूफेक्चरिंग एवं रोजगार को वापिस लायेंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने अपने नीतिगत निर्णयों में सबसे पहला निर्णय 'बाय अमेरिकन–हायर अमेरिकन' का किया। इस नीति के अंतर्गत उन्होंने चीन एवं अन्य देशों से होने वाले आयातों के खिलाफ आयात शुल्क बढ़ा दिये। उनकी इस नीति के परिणाम आने के बाद राष्ट्रहित में सरंक्षणवाद अपनाने के बारे में दुनिया भर में एक बहस शुरू हुई है।

इससे स्वदेशी जागरण मंच के सिद्धांतों, जिनके लिए वो पिछले 26 सालों से ज्यादा समय से लड़ रहा है, की प्रासंगिकता सिद्ध हुई है। भारत ने भी पिछले कुछ समय से चीन से आने वाले 100 से भी ज्यादा उत्पादों पर एंटी डंपिंग डयूटी लगाई है ताकि घरेलू उद्योगों को बचाया जा सके। इसके अलावा सरकार ने कई वस्तुओं पर आयात शुल्क भी बढ़ाये हैं। आयात शुल्कों में यह वृद्धि डब्ल्यूटीओ के समझौतों के अनुरूप ही है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि देश में तथाकथित उदारवादी लोग आयात शुल्क बढ़ाने और 'एंटी डंपिंग डयूटी' लगाने की इस कार्यवाही का विरोध कर रहे है। रोचक बात यह है कि डब्ल्यूटीओ समझौतों के अनुरूप होने के कारण सरकार की इस कार्यवाही का चीन भी विरोध नहीं कर पाया।

स्वदेशी जागरण मंच सरकार के द्वारा की गई इस कार्यवाही का समर्थन करता है, जिन उद्योगों को आयात शुल्क बढ़ाने के कारण फायदा हुआ है, उन्होंने भी सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। इसके कारण उत्पादन और रोजगार में सुधार के लक्षण दिखाई देने लगे है। स्वदेशी जागरण मंच सरकार से आग्रह करता है कि मुक्त व्यापार के इन तथाकथित समर्थकों और निहित स्वार्थों के सामने ना झुके और इस नीति को आगे बढ़ाये। ❑

फ्लिपकार्ड–वालमार्ट के बीच हो रहे सौदे के विरोध में स्वदेशी जागरण मंच ने प्रधानमंत्री को पत्रा लिखकर हस्तक्षेप करने की मांग की है। स्वदेशी पत्रिका के पाठकों के लिए प्रस्तुत है स्वदेशी जागरण मंच का पत्र –

माननीय श्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री, भारत सरकार
साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल्स, नई दिल्ली–110011

आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी,

हम बहुत भारी दिल से वैश्विक खुदरा कंपनी वाल्मार्ट द्वारा कानूनों का उल्लंघन करने तथा भारतीय बाजार में घुसपैठ कर राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाने, विषयक शिकायत पत्र आपको लिख रहे है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह अमरीका की विशालकाय कंपनी वालमार्ट, फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सिंगापुर व भारत की नियंत्रण हिस्सेदारी खरीद रही है, जिसे सिंगापुर और भारत स्थित उसकी सहायक कंपनियों द्वारा चलाने की योजना है। स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की आपसी सहमति है कि मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई न केवल उद्यमशीलता को मार देगा, बल्कि यह किसान विरोधी व्यवहार है जो बाजार में रोजगार निर्माण के अवसरों को भी खत्म कर देगा। इसलिए इसे बाहर रखा गया है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वॉलमार्ट भारतीय बाजार पर हमला करने के लिए नियमों का उल्लंघन कर ई–कॉमर्स के रास्ते घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि दुनिया में कहीं भी वॉलमार्ट प्लेटफार्म मॉडल पर काम नहीं करता।

हम अन्य देशों के अनुभव से जानते हैं कि जहां भी ऐसी घरेलू कंपनियां मौजूद थीं, वे सभी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) के हाथ बेच दी गई। दुनिया भर में वॉलमार्ट और कोस्को जैसे दिग्गजों ने इन कंपनियों पर एक तरह से कब्जा कर लिया है। यह सौदा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आश्चर्य की बात नहीं है। यही खतरा अब हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। फ्लिपकार्ट के जरिये वालमार्ट भारतीय बाजार को अपने कब्जे में करने का सुनियोजित षडयंत्र रच रहा है। ये घटनाएं हमें इस पत्र को लिखने के लिए मजबूर करती हैं। यह एक अनैतिक और राष्ट्रीय हितों के साथ–साथ देश के कानून के उल्लंघन का भी मामला है।

फ्लिपकार्ट के माध्यम से यह न केवल एक चोर दरवाजे से वालमार्ट का आगमन है, बल्कि भारतीय बाजार में उसके घुसपैठ की कोशिश भी है। इससे छोटे और मध्यम व्यवसाय, छोटी दुकानें और इन उद्यमों से अधिक नौकरियां पैदा करने का मौका खत्म हो जाएगा। इनमें से अधिकतर छोटे उद्यमी पहले से ही अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहे हैं। ऐसे में वालमार्ट के आने से उनके लिए और समस्याएं पैदा होगी।

आशा करते हैं कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि समाज के निचले हिस्से तक के लोगों के हितों की रक्षा की जाये। गौरतलब है कि वालमार्ट चीनी वस्तुओं का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है। चीन से माल खरीदने वाले छः देशों के बाद वालमार्ट कंपनी का स्थान सातवां है। यह कंपनी चीनी उत्पादों को ओर बढ़ावा देगी। जिससे हमारे छोटे और मध्यम उद्यमों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा तथा हमारे महत्वाकांक्षी योजना 'मेक इन इंडिया' को भी प्रभावित करेगा। हम सभी जानते हैं कि मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में वालमार्ट की अधिक रुचि है, ऐसे में दोनों (वालमार्ट व फ्लिपकार्ट) का सौदा किसानों के हितों को भी नुकसान पहुंचायेगा।

भारत के किसान, किसान उत्पादक संगठनों के जरिये प्रशिक्षित होने की प्रक्रिया में हैं। उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) से निपटने तथा उनके उत्पादन और उसके उचित मूल्य को समझने में अभी समय लगेगा। ऐसे में वालमार्ट के आने से उनकी यह सारी कोशिश बेकार जायेगी। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए आपकी प्रतिबद्धता का सम्मान करते हुए हम सभी आपके साथ हैं। लेकिन स्वदेशी जागरण मंच का यह स्पष्ट मानना है कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां न सिर्फ इस सपने को चकनाचूर कर देगी, बल्कि किसानों को उनकी फसलों के लिए मौजूदा बाजार ढांचे को नष्ट कर उन्हें भूखा मरने के लिए छोड़ देगी।

स्वदेशी जागरण मंच की प्रारंभ से ही यह प्रतिबद्धता रही है कि किसान को न केवल अधिक कमाई करनी चाहिए, बल्कि उसे अपने उपज को बेचने के लिए भी स्वतंत्र होना चाहिए। इससे भारत की खाद्य सुरक्षा नीति को भी पर्याप्त बल मिलता है। लेकिन वालमार्ट के आने से इस लक्ष्य को भी नुकसान पहुंचेगा। हमारे अधिकांश किसान बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नक्शे कदम पर चलने के लिए बाध्य होंगे, जो कि निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय हित में नहीं होगा।

भारत रणनीतिक रूप से विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में ई–कॉमर्स पर चर्चा का विरोध करता रहा है और स्वदेशी जागरण मंच हमेशा इसका हिमायती रहा है। इस रणनीति को चुनने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हमें अपने कानूनों और नियमों को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि भारतीय हितों को सर्वोत्तम रूप से संरक्षित किया जा सके। लेकिन वालमार्ट की यह घुसपैठ हमारे उद्देश्य को विफल कर देगी। वर्तमान में मजबूत प्रहरी की अनुपस्थिति, नियामक लोकपाल के न होने तथा कुछ नौकरशाहों की मिलीभगत से कई तरह के उल्लंघनों को भी एक तरह से अनुमति दी गई है। ई–कॉमर्स के माध्यम से बी 2 बी व्यापार के लिए कोई नियम निर्धारित नहीं है, इसलिए उनके कामकाज पर कोई नियंत्रण नहीं है। स्वदेशी जागरण मंच का कहना है कि नियमों और विनियमों की अनुपस्थिति में, फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मित्रा जबाँग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इसी तरह की कंपनियों को मौजूदा या नए निवेशकों से सीधे या परोक्ष रूप से किसी भी धन को बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

फ्लिपकार्ट के ऑपरेशन संदेह से परे नहीं हैं, उनकी समूह कंपनियां, जैसे फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड, जो भारत में बड़े व्यवसाय करते हैं, ने वर्ष 2016–2017, 2015–2016 के लिए अपने विवरणी का रिटर्न भी दायर नहीं किया है, केवल आंशिक खुलासा ही किया है। यह बहुत खतरनाक होगा, अगर हम उन्हें धन जुटाने, संपत्तियों को स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं, वह भी वॉलमार्ट जैसी कंपनी के लिए। डीआईपीपी प्रेस नोट 3/2016 में बताये गये एफडीआई नियमों पर स्पष्टीकरण के उल्लंघन के डीआईपीपी, प्रवर्तन निदेशालय और आरबीआई के साथ शिकायतों की श्रृंखला रही है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है।

पिछले कुछ सालों में, फ्लिपकार्ट ने बी2बी, ई–कॉमर्स और मार्केटप्लेस स्ट्रक्चर के तहत कंपनियों का एक जाल बिछाया है, जिसकी जांच सरकारी तंत्र द्वारा नहीं की जा सकी।

फ्लिपकार्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि फ्लिपकार्ड की एक थोक व्यापार कंपनी है, ने आयकर अधिकारियों के समक्ष इस बात को स्वीकार किया है कि कंपनी थोक मूल्य पर माल खरीदकर बाद में उसे कम दाम पर फ्लिपकार्ड.कॉम पर बेचती है। यह अप्रत्यक्ष रूप से डीआईपीपी प्रेस नोट 3/2016 में निर्धारित नियमों और सिद्धांतों का उल्लंघन है। इतना ही नहीं यह विदेशी धन का उपयोग करने का एक खतरनाक व्यवसायिक अभ्यास भी है। लेनदेन में जीएसटी का भुगतान नहीं करने, आयकर का भुगतान नहीं करने और पुस्तक की हानि के कारण विदेश आधारित कंपनी के मूल्यों में वृद्धि होती है, जो कि भारत के लिए हानिप्रद है।

स्वदेशी जागरण मंच सभी देशवासियों के साथ, कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करने और इस संबंध में उचित कार्रवाई करने के लिए आपकी ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं।

आभार सहित

डॉ. अश्वनी महाजन

अखिल भारतीय सहसंयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

(पेज 7 से आगे...)

एयर इंडिया के विनिवेश पर...

में फंसे हुए भारतीयों को स्वदेश वापिस लाने का भी काम किया है और सेनाओं और युद्ध के समय भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहण किया है। ऐसे रूटों पर जहां निजी कंपनियां लाभ नहीं होने के कारण सेवाएं देने से मना कर देती हैं, एयर इंडिया ही वहां कार्यरत होता है। सभी राज्यों की राजधानियों को वायु यातायात की सुविधा से लैस करने का काम भी एयर इंडिया करता है। और दूर–दराज के क्षेत्रों में यही मद्द करता है। आज जब निजी क्षेत्र की बड़ी–बड़ी कंपनियों द्वारा लिए गए ऋणों की अदायगी में बैंकों द्वारा भारी छूटें दी जा रही हैं, एक सरकारी उपक्रम होने के कारण एयर इंडिया पर दोहरे मापदंड क्यों? क्यों उसे ये सुविधाएं नहीं दी सकती? सरकार को विचार करना चाहिए।

गौरतलब है कि 1983 में ब्रिटिश एयरवेज की भी ऐसी ही स्थिति थी, तब ब्रिटिश एयरवेज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और पुराने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति का प्रोत्साहन देकर मानव संसाधनों पर लागत तो कम की ही अन्य लागतों पर भी नियंत्रण लगाकर ब्रिटिश एयरवेज को फायदे में पहुंचा दिया। उसके बाद सरकार ने जब उस कंपनी के शेयर बाजार में उतारे तो उसके लिए 11 गुणा ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए। वर्तमान परिस्थितियों में एयर इंडिया को भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ाया जा सकता है। ❑❑

एयर इंडिया को बचाने के लिए स्वदेशी जागरण मंच की पहल

सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया को फिर से खड़ा करने के लिए आरएसएस से जुड़ा स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) इस महीने नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु के सामने रिपोर्ट पेश करेगा, जिसमें कंपनी को घाटे से उबारने के लिए 'वैकल्पिक तरीके' अपनाने के सुझाव दिए होंगे। मंच पहले भी एयर इंडिया के विनिवेश पर विरोध जता चुका है। सूत्रों ने कहा कि हाल ही में प्रभु ने एयर इंडिया में हिस्सेदारी की बिक्री पर चर्चा के लिए एसजेएम के सह–संयोजक अश्निनी महाजन से मुलाकात की। जानकारों की माने तो 'महाजन के नेतृत्व में पांच सदस्यीय दल रिपोर्ट तैयार कर रहा है। रिपोर्ट में एयर इंडिया को वैकल्पिक तरीकों से पुनर्जीवित करने का सुझाव होगा। दल इस महीने अपनी रिपोर्ट प्रभु के सामने रखेगा।'

सूत्र ने बताया कि कंपनी के विनिवेश पर कोई भी फैसला लेने से पहले रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा। महाजन ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि वह और चार अन्य अर्थशास्त्री मिलकर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। मंच ने पहले भी एयर इंडिया में हिस्सेदारी बेचने के बजाए कर्ज का भुगतान करने के लिए उसकी परिसंपत्तियां को बेचने का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया को परिचालन से मुनाफा हो रहा है लेकिन कर्ज के कारण घाटे में चल रही है. इसलिए सरकार को हिस्सेदारी बेचने के बजाए कर्ज कम करने के लिए उसकी जमीन बेचनी चाहिए।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सर संघचालक मोहन भागवत के बयान के बाद महाजन की प्रतिक्रिया को प्रासंगिक माना जा रहा है. भागवत ने एयर इंडिया को विदेशी खरीदार को बेचने का विरोध किया था।

https://hindi.firstpost.com/business/swadeshi-jagran-manch-preparing-report-on-alternative-ways-to-revive-air-india-pr-110030.html

वालमार्ट–फ्लिपकार्ड डील से 22 करोड़ परिवार होंगे प्रभावित

स्वदेशी जागरण मंच ने अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट और ई–कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के सौदे का विरोध किया है। मंच के पदाधिकारियों ने रविवार को कहा कि वॉलमार्ट के रिटेल ई–कॉमर्स के क्षेत्र मे उतरने से देसी कारोबारियों व उद्योगों को भारी नुकसान होगा। स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक अरुण ओझा ने कहा कि इस सौदे से छोटे कारोबारियों का कारोबार चौपट हो जाएगा और इससे देशभर में 20–22 करोड़ परिवार प्रभावित होंगे।

ओझा ने कहा, 'हमारा विरोध देश में ई–कॉमर्स के क्षेत्र में विदेशी निवेश को लेकर है। वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट के सौदे से वॉलमार्ट ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के जरिए देश के बाजार पर इस विदेशी कंपनी का प्रभुत्व कायम हो जाएगा और छोटे–छोटे कारोबारियों का कारोबार चौपट हो जाएगा।' मंच के राष्ट्रीय सह–संयोजक अश्विनी महाजन ने कहा, 'ई–कॉमर्स के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को अनुमति नहीं है। फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट का सौदा कानूनी रूप से अवैध होगा।' उन्होंने कहा कि विदेशी निवेश इक्विटी के जरिए होना चाहिए। रिटेल कारोबार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उचित नहीं है। लिहाजा, सरकार को इस पर रोक लगाने के लिए कदम उठाना चाहिए। उन्होंने इस सौदे से होने वाले नुकसान का आकलन करते हुए कहा कि ई–कॉमर्स के क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए कोई विनियामक नहीं है। ऐसे में वॉलमार्ट जैसे विदेशी कंपनियों के इसमें उतरने से घरेलू उद्योग और व्यापार तबाह हो जाएगा.

महाजन ने कहा, 'वॉलमार्ट पहले से ही होलसेल और लॉजिस्टिक्स में अपना साम्राज्य बना लिया है। फ्लिपकार्ट के साथ इसके सौदे से रिटेल कारोबार में इसका प्रभुत्व कायम हो जाएगा।' उन्होंने कहा कि वॉलमार्ट चीनी वस्तुओं का सबसे बड़ा विक्रेता है। इससे देशी बाजार में चीनी वस्तुओं की आमद बढ़ जाएगी जिससे देशी उद्योग प्रभावित होगा।

महाजन ने कहा, 'फ्लिपकार्ट–वॉलमार्ट मसले को लेकर विरोध के मद्देनजर हमारी बैठकें चल रही हैं। हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इसके बाद हम सरकार को अपनी चिंताओं से अवगत कराएंगे। उन्होंने बताया कि अगले एक–दो दिन में स्वेदशी जागरण मंच की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु को वे इस संबंध में पत्र लिखकर फ्लिपकार्ट–वॉलमार्ट सौदे से होने वाले नुकसान से उन्हें अवगत कराया जाएगा।

महाजन ने कहा, 'हम केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु से मिलकर उन्हें अपनी चिंताओं से अवगत कराएंगे।' सूत्रों के मुताबिक रिटेल कारोबार क्षेत्र की दिग्गज अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट ई–कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट में 75 फीसदी शेयर खरीदने जा रही है। फ्लिपकार्ट की बोर्ड ने इस सौदे को अनुमति दे दी है।

http://hindi.catchnews.com/business-economy/swadeshi-jagran-manch-said-22-million-families-will-be-affected-by-wal-mart-flipkart-deal-111916.html

नचिकेत मोर को रोकने के लिए मंच ने लिखी मोदी को चिट्ठी

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड में नचिकेत मोर की नियुक्ती से खुश नहीं है। यही वजह है कि संगठन ने नचिकेत मोर की नियुक्त को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। स्वदेशी जागरण मंच ने अपने पत्र में नचिकेत की नियुक्ति को रोकने के लिए प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप की मांग की है। पत्र में हितों का टकराव को रोकने के लिए पीएम मोदी के हस्तक्षेप की गुजारिश की गई है।

स्वदेशी जागरण मंच ने नचिकेत मोर की नियुक्ति को हितों के टकराव का मामला बताआ है और उनकी नियुक्ति पर भी सवाल उठाए हैं। स्वदेशी जागरण मंच ने कहा कि नचिकेत मोर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (BMGF) के फुल टाइम रिप्रजेंटेटिव रहे हैं, जिस पर गृह मंत्रालय की कड़ी नजर है। साथ ही यह संगठन लगातार विदेशी सोर्स से फंड पा रहा है।

स्वदेशी मंच ने कहा कि स्वास्थ्य और कृषि से संबंधित सरकारी नीतियों को प्रभावित करके फाउंडेशन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पक्ष में काम कर रहा है। यही वजह है कि इन आरोपों के कारण गृह मंत्रालय उनकी निगरानी रखता है। स्वदेशी जागरण मंच ने कहा कि बीएमजीएफ भारत में रिजर्व बैंक और इंडिया की अनुमति से कार्य करता है। अगर उनकी नियुक्ति होती है तो हितों के टकराव का मामला हो सकता है।

गौरतलब है कि स्वदेशी जागरण मंच राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ का ही एक मंच है, जो समय–समय पर ऐसे मुद्दों पर अपनी आवाजें बुलंद करते रहता है।

https://khabar.ndtv.com/news/india/swadeshi-jagaran-manch-writes-letter-to-pm-modi-over-appointment-of-nachiket-mor-in-rbi-1837801

लघु उद्योग हैं अर्थव्यवस्था की रीढ़ः सतीश कुमार

स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह विचार विभाग के प्रमुख सतीश कुमार ने लघु उद्योगों को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया है। उन्होंने कहा कि देश की कुल जीडीपी में करीब 45 फीसद का योगदान लघु उद्यमियों का है। सतीश कुमार लघु उद्योग भारती के रजत जंयती स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित कर रहे थे। समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर थे, अध्यक्षता उद्यमी पप्पूजीत... सह सरना ने की और विशिष्ट अतिथि के रूप मे लघु उद्योग भारती हरियाणा के उपाध्यक्ष अरुण बजाज उपस्थित थे। सतीश कुमार ने स्वदेशी को बढ़ावा देने की अपील की, उन्होंने कहा कि स्वदेशी का चलन बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा लघु उद्योगों को ही फायदा पहुंचेगा।

मुख्य अतिथि कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि आज के परिवेश मे भारतीय लघु उद्यमी भारतीय अर्थव्यवस्था हो, रोजगार देना हो या कौशल विकास की बात हो सब में आगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि जहां एक करोड़ के निवेश पर सात लोगों को रोजगार मिलता है वहीं लघु उद्योग मे उतने ही निवेश पर 59 लोगों को रोजगार मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया के जरिए लघु उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने अनधिकृत क्षेत्र में चल रहे उद्योगों को मान्यता दिलवाने का आश्वासन देते हुए कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री से बात की जाएगी।

संस्था के प्रदेश कोषाध्यक्ष मनोज रूंगटा ने ई–वे बिल में होने वाली परेशानियों के निदान की जानकारी दी। संस्था के अध्यक्ष रवि भूषण खत्री ने अतिथियों का स्वागत किया और स्मृति चिन्ह भेंट किए। अरुण बजाज ने लघु उद्योग भारती की

राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी दी। मंच संचालन लघु उद्योग भारती के महासचिव राकेश गुप्ता ने किया, धन्यवाद उपाध्यक्ष अनिल प्रताप सिह ने किया।

कार्यक्रम में सीए गौतम चौधरी, बलबीर सिंह, विजय गुप्ता, आर पी खुल्लर, रमेश झंवर, आर के चावला, एलडी सचदेवा, पवन गुप्ता, अमृत पाल कोचर, महेंद्र सर्राफ, ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रदीप बंसल, स्वदेशी जागरण मंच के प्रदेश संयोजक सत्येंद्र सौरोत, विभाग संपर्क प्रमुख दीपक अग्रवाल, संजय अरोड़ा, जिला संघ चालक तथा एफआइए के उपाध्यक्ष ऋषि अग्रवाल उपस्थित थे।

https://www.jagran.com/haryana/faridabad-industry-17879539.html

ईरान परमाणु समझौते से अलग हुआ अमेरिका, दुनियाभर ने किया विरोध

अमेरिका ने ईरान परमाणु समझौते से खुद को अलग कर लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की। ट्रंप को मनाने की सभी कोशिशें नाकाम रहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समझौते से अमेरिका के अलग होने के बाद मध्य पूर्व में हथियारों की दौड़ तेज होने का खतर बढ़ सकता है। ईरान और छह अन्य वैश्विक शक्तियों के बीच हुए परमाणु समझौते के तहत ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करने को राजी हुआ था और बदले में ईरान पर लंबे समय से लगे आर्थिक प्रतिबंधों में ढील दी गई थी।

ट्रंप ने व्हाइट हाउस से टेलीविजन पर प्रसारित अपने संबोधन में अमेरिका के इस समझौते से अलग होने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वह ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों से संबंधित प्रतिबंधों में ढील देने के समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे और समझौते के तहत तेहरान पर से हटाए गए प्रतिबंधों को दोबारा लागू करेंगे।

ट्रंप ने साथ ही कहा कि अमेरिका ईरान के साथ व्यापारिक संबंध रखने वाले देशों के खिलाफ भी कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। ट्रंप ने ईरान और संयुक्त समग्र कार्ययोजना (जीसीपीओए) परमाणु समझौते की फिर से आलोचना करते हुए कहा कि यह समझौता ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने या क्षेत्र में आतंकवाद को बढ़ावा देने से रोकने में विफल रहा है।

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका तेहरान पर बेहद कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा। उन्होंने साथ ही कहा कि जो भी देश परमाणु हथियार बनाने में ईरान की सहायता करेंगे अमेरिका उन पर भी कड़े प्रतिबंध लगाएगा। व्हाइट हाउस ने बाद में कहा कि ट्रंप ने अपने प्रशासन को जेसीपीओए से संबंधित प्रतिबंध फिर से लगाने की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है।

ईरान और छह वैश्विक शक्तियों अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस, फ्रांस और जर्मनी के बीच जुलाई 2015 में वियना में ईरान परमाणु समझौता हुआ था। ट्रंप के इस समझौते से अलग होने के फैसले से विश्व भर में तनाव व्याप्त हो गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रों ने ट्रंप के इस फैसले पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि अमेरिका के इस फैसले से फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन निराश हैं।

मैक्रों, मर्केल और थेरेसा मे ने ईरान परमाणु समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता कायम रखने की बात दोहराते हुए कहा है कि यह समझौता हमारी साझा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वॉशिंगटन स्थित हथियार नियंत्रण संघ ने भी ट्रंप के फैसले की आलोचना की है। इस बीच चीन के पश्चिम एशिया में विशेष दूत गोंग शिओशेंग ने कहा है कि ईरान परमाणु समझौते में शामिल सभी पक्षों को इससे जुड़े रहना और विवाद को खत्म करने के लिए संवाद तथा बातचीत का सहारा लिया जाना चाहिए। ईरान से आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शिओशंग ने ईरान के अधिकारियों से मुलाकात के बाद पत्रकारों से कहा कि चीन ईरान परमाणु समझौते में शामिल सभी पक्षों के साथ सहयोग बढ़ाने का इच्छुक है। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने ईरान परमाणु समझौते से अलग होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के इस कदम पर यूरोपीय संघ एकजुट रुख अपनाएगा। टस्क ने ईरान परमाणु समझौते से अलग होने की ट्रंप की घोषणा के कुछ ही मिनटों बाद ट्वीट किया, ईरान समझौते और व्यापार को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर यूरोपीय संघ एकजुट फैसला लेगा।

https://money.bhaskar.com/news/MON-ECN-INTE-ECNM-trump-pulls-us-out-from-iran-nuclear-deal-5869381-PHO.html

नरेंद्र मोदी दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल

फोर्ब्स ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दुनिया के 10 शक्तिशाली लोगों में शामिल किया है। मोदी को 9वां स्थान मिला है। वहीं, इस लिस्ट में रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन को पीछे छोड़ते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहला स्थान हासिल किया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब चीन के राष्ट्रपति ने पुतिन को पीछे छोड़ यह रुतबा हासिल

किया। फोर्ब्स की तरफ से साल 2018 के लिए उन 75 सबसे पावरफुल लोगों की लिस्ट जारी की गई है, जिन्होंने दुनिया में बदलाव लाया।

फोर्ब्स का कहना है कि मोदी दुनिया की दूसरी सर्वाधिक आबादी वाले देश का सबसे लोकप्रिय चेहरा हैं। उसने मोदी सरकार के नवंबर 2016 के उस फैसले का हवाला दिया जिसमें ब्लैकमनी और करप्शन को रोकने के लिए दो नोटबंदी का फैसला किया गया था। फोर्ब्स का कहना है कि हाल के कुछ सालों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप और चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ आधिकारिक यात्रा कर बतौर ग्लोबल लीडर अपनी प्रोफाइल मजबूत की है। फोर्ब्स के मुताबिक, मोदी की छवि क्लाइमेंट चेंज के मसले के समाधान के वैश्विक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उभरी है।

फोर्ब्स की सबसे शक्तिशाली लोगों की लिस्ट में लगातार चार साल तक टॉप पर रहने वाले पुतिन इस बार शी जिनपिंग से पिछड़ गए। उन्हें दूसरे स्थान ही मिला। जिनपिंग को टॉप रैंक मिलने की सबसे बड़ी वजह बीते मार्च में चीन के सविंधान में चीनी कांग्रेस की ओर किए गया संशोधन रहा। इसके बाद जिनपिंग का प्रभाव बढ़ा और देश का राष्ट्रपति रहने की निश्चित अवधि की बाध्यता उनके लिए समाप्त हो गई। जिनपिंग को पहली बार यह रुतबा हासिल हुआ है। फोर्ब्स का कहना है कि चीन के संस्थापक कहे जाने वाले माओ के बाद से सिर्फ जिनपिंग के व्यक्तित्व में ही इस तरह का प्रभाव दिखाई दिया है।

फोर्ब्स का कहना है कि धरती पर करीब 7.5 अरब लोग हैं लेकिन इनमें से ये 75 महिलाएं और पुरुष दुनिया का रूख बदलते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवार लोगों को लेकर फोर्ब्स की सालाना रैंकिंग में प्रत्येक 10 करोड़ लोगों में से एक को चुना जाता है, जिसका एक्शन खास मायने रखता है।

फोर्ब्स की इस लिस्ष्ट में 67 वर्षीय पीएम नरेंद्र मोदी फेसबुक सीईए मार्क जकरबर्ग (13वां रैंक), ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे (14वां रैंक), चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग (15वां रैंक) और एप्पल के सीईओ टिम कुक (24वां रैंक) से आगे हैं।

फोर्ब्स की इस लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के चेयरमैन मुकेश अंबानी एक और भारतीय हैं, जिन्हें 41.2 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 32वीं रैंक मिली है। वहीं, माइक्रोसॉफ्ट के भारत में पैदा हुए सीईओ सत्य नडेला को इस सूची में 40वां स्थान दिया गया है।

1. शी जिनपिंग (चीन के राष्ट्रपति), 2. ब्लादिमीन पुतिन (रूस के राष्ट्रपति), 3. डोनॉल्ड ट्रंप (अमेरिका के राष्ट्रपति), 4. एंजेला मर्केल (जर्मन चांसलर), 5. जेफ बेजोस (फाउंडर अमेजन), 6. पोप फ्रांसिस (पोप रोमन कैथलिक चर्च), 7. बिल गेट्स (कोफाउंडर, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन), 8. मोहम्मद बिन सलमान अल सउद (क्राउन प्रिंस सऊदी अरब), 9. नरेंद्र मोदी (प्रधानमंत्री, भारत), 10. लैरी पेज (कोफाउंडर अल्फाबेट)।

https://money.bhaskar.com/news/MON-ECN-INTE-ECNM-infog-narendra-modi-among-top-10-most-powerful-people-in-the-world-says-forbes-5869403-PHO.html

सौ फीसद बायो एथेनॉल वाहन को मिली मंजूरी

सरकार ने सौ फीसद बायो एथेनॉल से बने वाहनों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि उनके मंत्रालय ने वाहन निर्माता कंपनियों बजाज और टीवीएस को इस दिशा में कदम बढ़ाने की अनुमति दे दी है। बायो एथेनॉल धान और गेहूं के भूसे से बनता है।

एक तेलुगु समाचार चौनल के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'मैंने बजाज और टीवीएस के प्रबंधन को एथेनॉल आधारित बाइक और ऑटो रिक्शा बनाने के लिए कहा था। मेरे निर्देश पर उन्होंने इनका निर्माण किया। मैं उन्हें अनुमति दे रहा हूं कि अब ऑटो रिक्शा, बाइक और स्कूटर 100 फीसद बायो एथेनॉल पर चलेंगे।'

गडकरी ने कहा कि कोई इस्तेमाल नहीं होने के कारण धान की पुआल पंजाब और हरियाणा में जला दी जाती है। इससे प्रदूषण भी फैलता है। बायो एथेनॉल से चलने वाले वाहनों के विकास से इस पुआल का इस्तेमाल किया जा सकेगा। एक टन पुआल से 280 लीटर एथेनॉल बनाया जा सकता है। गडकरी ने सरकार के अन्य कदमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा, 'हम हर साल 40,000 हजार करोड़ रुपये के टिंबर, चार हजार करोड़ रुपये की सुगंधित लकड़ियों, 35 हजार करोड़ रुपये के पेपर पल्प और 35 हजार करोड़ रुपये के न्यूजप्रिंट का आयात करते हैं। इस तरह कुल मिलाकर एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का आयात लकड़ियों से संबंधित है।' गडकरी ने कहा कि सरकार ने इसे कम करने पर जोर दिया है। केंद्र ने किसानों को बांस की खेती के लिए प्रोत्साहित किया है, जिससे आयात कम करने में मदद मिली है। पहली बार बांस को पेड़

की श्रेणी में रखा गया है। मीडिया पर राजनीतिक प्रभाव को लेकर भी गडकरी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोग चाहते हैं कि मीडिया स्वतंत्र और पक्षपात रहित हो।

https://www.jagran.com/business/biz-100pc-bio-ethanol-vehicles-receives-nod-17918640.html

अब बिना आधार भी मिलेगा मोबाइल सिम

अब आपको मोबाइल सिम खरीदने के लिए आधार ही देने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने सभी मोबाइल ऑपरेटर्स को निर्देश जारी किए हैं कि ग्राहक आधार कार्ड के बिना भी सिम खरीद सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार का यह भी कहना है कि जहां तक ग्राहकों की पहचान की जांच का सवाल है तो इसके लिए वोटर आईडी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस भी लिये जा सकते हैं। सरकार ने मोबाइल कंपनियों को इन निर्देशों का तुरंत पालन करने का आदेश दिया है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जब तक कोर्ट आधार के मामले में कोई आखिरी फैसला नहीं ले लेता है, तब तक सिम कार्ड के लिए आधार अनिवार्य नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ऐसी रिपोर्ट आई थीं कि लोगों को बिना आधार सिम नहीं दी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, टेलीकॉम मंत्रालय की ओर से टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी कर कहा गया है कि वह आधार कार्ड न होने की स्थिति में किसी ग्राहक को सिम खरीदने से मना ना करें। इसके बदले वह केवाईसी के अन्य फॉर्म और डॉक्युमेंट्स ले सकते हैं।

https://money.bhaskar.com/news/MON-ECN-POLI-ECNM-now-aadhaar-is-not-mandatory-to-buy-mobile-sim-5864475-NOR.html

सैन्य खर्च में चीन से बहुत पीछे है भारत

सैन्य खर्च के मामले में भारत दुनिया के टॉप–5 देशों में शामिल हो गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिप्री) ने सैन्य मामलों में सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देशों की एक लिस्ट जारी की है। इसमें फ्रांस की जगह भारत पांचवें स्थान पर रखा गया है। लेकिन, चीन के मुकाबले भारत का सैन्य खर्च 3.6 गुना कम है। सिप्री के मुताबिक, रक्षा क्षेत्र में खर्च के मामले में अमेरिका और चीन अभी भी पहले और दूसरे नंबर पर हैं।

पिछले साल दुनियाभर के सैन्य खर्च में 2016 के मुकाबले 1.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई। ये आंकड़ा कुल 1.73 ट्रिलियन डॉलर्स (करीब 115 लाख करोड़ रुपए) पर पहुंच

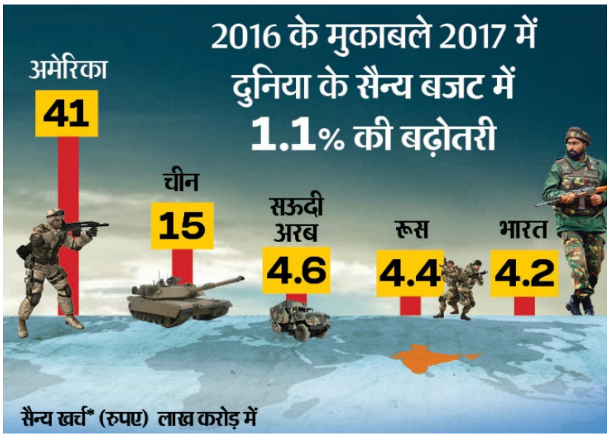

गया है। ये दुनियाभर की जीडीपी का 2.2 प्रतिशत है। बता दें कि 2016 में कुल सैन्य खर्च 1.68 ट्रिलियन डॉलर्स था।

देश	कुल सैन्य खर्च' (रुपए)
अमेरिका	40 लाख 68 हजार करोड़
चीन	15 लाख 19 हजार करोड़
सऊदी अरब	4 लाख 60 हजार करोड़
रूस	4 लाख 40 हजार करोड़
भारत	4 लाख 26 हजार करोड़
फ्रांस	3 लाख 86 हजार करोड़
ब्रिटेन	3 लाख 13 हजार करोड़
जापान	3 लाख 3 हजार करोड़
जर्मनी	2 लाख 95 हजार करोड़
दक्षिण कोरिया	2 लाख 61 हजार करोड़

रिपोर्टः स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट।

रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन, भारत और सऊदी अरब जैसे देश लगातार अपने सैन्य खर्च को बढ़ा रहे हैं। पिछले साल चीन ने अपना सैन्य खर्च 5.6: (करीब 80 हजार करोड़ रुपए) तक बढ़ाया है। 2017 में चीन का कुल सैन्य खर्च 15 लाख 19 हजार करोड़ रहा।

वहीं, खर्च कम करने के मामले में रूस सबसे आगे रहा। रूस ने 2016 में खर्ची गई राशि के मुकाबले 2017 में 20: कम सैन्य खर्च किया। पिछले साल रूस का कुल सैन्य खर्च 66.3 बिलियन डॉलर्स (करीब 4 लाख 40 हजार करोड़ रुपए) तक सीमित कर दी है।

वहीं, भारत ने भी पिछले साल अपना सैन्य खर्च 5.5: तक बढ़ाया है। भारत ने 2017 में 63.9 बिलियन डॉलर्स (करीब 4 लाख 26 हजार करोड़ रुपए) खर्च किए। हालांकि, भारत का कुल सैन्य खर्च चीन के मुकाबले 3.6 गुना कम है। 2017 में चीन का खर्च 15 लाख 19 हजार करोड़ रहा, वहीं भारत ने अपना बजट 4 लाख 26 हजार करोड़ रूपए रखा था।

https://www.bhaskar.com/indian-national-news-in-hindi/news/india-reaches-5th-spot-in-top-military-spenders-amid-us-and-china-at-top-5864803.html

फ्लिपकार्ट–वालमार्ट सौदे के विरोध में स्वदेशी जागरण मंच

स्वदेशी जागरण मंच ने फ्लिपकार्ट–वालमार्ट सौदे का विरोध किया है। मंच ने सौदे को देशहित के विरुद्ध बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है। स्वदेशी जागरण मंच ने आरोप लगाया कि खुदरा व्यापार क्षेत्र की अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट में 16 अरब डालर के बहुलांश हिस्सेदारी के अधिग्रहण की पहल के साथ भारत में पिछले दरवाजे से प्रवेश का प्रयास कर रही है। मंच ने आरोप लगाया है कि इससे छोटे और मझोले कारोबारी और छोटे दुकानदारों पर गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उनके समक्ष अस्तित्व का संकट खड़ा होगा।

मंच ने प्रधानमंत्री को इस विषय पर पत्र लिखा है और उनसे यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि समाज के निचले पायदान के लोगों के हितों के साथ देश के कृषि क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

स्वदेशी जागरण मंच ने यह पत्र ऐसे समय में लिखा है जब वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में 77 प्रतिशत हिस्सेदारी अधिग्रहित कर ली है। मंच ने आरोप लगाया है कि वॉलमार्ट ई–कामर्स मार्ग को अपनाकर विदेशी कंपनियों पर मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रवेश की पाबंदी के नियमों को छका रही है।

पत्र के मुताबिक, मल्टीब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) की अनुमति नहीं होने के कारण वालमार्ट ई–कॉमर्स का रास्ता अपना रही है। यह सौदा छोटे और मझोले कारोबारियों और दुकानदारों को खत्म करेगा और रोजगार सृजन के अवसर भी कम करेगा। बहुत से छोटे कारोबारी अभी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। वालमार्ट के दखल के बाद उनके लिए हालात और मुश्किल होंगे। मंच ने इस सौदे में नियमों के उल्लंघन का मामला भी उठाया है।

स्वदेशी जागरण मंच के सह–संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने कहा, 'यह सौदा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आश्चर्यजनक नहीं। अब संकट हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है।' प्रधानमंत्री से दखल की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि वालमार्ट चीनी वस्तुओं के सबसे बड़े आयातकों में से है। यह सौदा मेक इन इंडिया अभियान के लिए भी घातक होगा। सूत्रों का कहना है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने स्वदेशी जागरण मंच को भरोसा दिलाया है कि मंत्रालय इस मामले पर विचार करेगा। ❑❑